सोशल मीडिया से जुड़ें
Parivehan_Vishesh

RNI No :- DELHIN/2023/86499
DCP Licensing Number :
F.2 (P-2) Press/2023

www.newsparivahan.com

परिवहन विशेष

वर्ष 02, अंक 24, नई दिल्ली । शनिवार, 06 अप्रैल 2024, मूल्य ₹ 5, पेज 8

देश का पहला ट्रांसपोर्ट दैनिक समाचार पत्र

आज का सुविचार

लड़ाई लड़ने वाला तो विजय प्राप्त करता है परंतु दूर से देखने वाला तो सिर्फ तालियां बजाता रह जाता है।

03 'बीजेपी ने किया शराब घोटाला, कई बड़े नेता शामिल', संजय सिंह का बड़ा दावा
06 पंजाब में अकाली-भाजपा गठबंधन टूटा
08 भी के पांडियन को मुख्यमंत्री कार्यालय से निष्कासित किया जाना चाहिए

टोलवा दिल्ली परिवहन विभाग में पिछले 5 वर्षों से आज तक के कार्यरत आला अधिकारियों के द्वारा जारी आदेशों/कार्यों की निष्पक्ष जांच की मांग करेगा

जानें आखिर क्यों और क्या है कारण और कोन से आदेश है जिसे जनता की जगह मिला फायदा किसी और को

संजय बाटला

1. सीसी कैमरे घोटाला,
2. डीटीसी बस घोटाला,
3. पैनिक बटन घोटाला,
4. जीपीएस/वीएलटीडी घोटाला,
5. आटो शाखा में मरे हुए व्यक्तियों के परमिट हस्तांतरण घोटाला,
6. हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट घोटाला,
7. डीटीसी की संपत्ति पर कब्जा करने का घोटाला,
8. महिला पिंक पास घोटाला
9. प्रदूषण के नाम से लोगो की वाहनों को उठाकर अपने प्रिय वाहन स्क्रैप डीलरो को सुपुर्द करने का घोटाला इत्यादि सभी घोटाले 2019 से आज तक में ही हुए, इन सभी घोटालों और साथ में अन्य घोटालों के लिए राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और उपराज्यपाल दिल्ली से जनवरी 2019 से जनवरी 2024 में कार्यरत परिवहन विभाग के आला अधिकारी (**आयुक्त और विशेष आयुक्त**) के द्वारा जारी सभी आदेशों/ निर्देशों की निष्पक्ष जांच की मांग करेगा टोलवा।

भूल सुधार : कल दिनांक 5 अप्रैल 2024 के अंक में प्रथम पृष्ठ पर प्रकाशित समाचार "विशेष परिवहन आयुक्त स्क्रैप पालिसी एस.ओ.पी. जारी होने के बाद भी नही जारी करना चाहते निर्धारित समय सीमा समाप्त व्यवसायिक वाहनों को एनओसी आखिर क्यों?" में 4 अप्रैल 2024 व 3 अप्रैल 2024 के स्थान पर भूलवश 4 अप्रैल 2014 व 3 अप्रैल 2014 प्रकाशित हो गया है। जिसके लिए प्रकाशन खेद व्यक्त करता है।

क्यों ना चुनाव का बहिष्कार करे ?

दिल्ली टैक्सी, टूरिस्ट ट्रांसपोर्टर्स एंड टूर ऑपरेटर एसोसिएशन, द्वारा आज राजीव कुमार, मुख्य चुनाव आयुक्त इलेक्शन कमिशन ऑफ़ इंडिया को ज्ञापन सौंपा.

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। दिल्ली के टैक्सी, बसों के मालिकों को 10 सालो से हो रहीं समस्यायों पर केंद्र और दिल्ली सरकार (सांसदों /विधयाको) ने ध्यान नहीं देने के कारण 2024 के चुनाव का क्यों ना बाहिष्कार करा जाए? हम दिल्ली के टैक्सी, बस मालिक, लगातार 10 सालो से केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के मंत्रियो, सांसदों और विधायको से उपेक्षित रहें हैं इन सब ने इन 10 सालो में ना तो मिलने का समय दिया और कभी कभार बड़ी मुश्किल से इन्होने मिलने का समय दें भी दिया तो हमारी जायज मांगो को इन्होने रद्दी की टोकरी में डाल दिया. **हमारी मुख्य मांगे थी :-**

1:- दिल्ली की आल इंडिया टूरिस्ट परमिट की टैक्सी बसों से स्पीड लिमिट डिवाइस हटना चाहिए क्योंकि इस स्पीड लिमिट डिवाइस की वजह से एक्सप्रेस वे और हाई वे पर हमारी टूरिस्ट टैक्सी बसें 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ़्तार से ज्यादा नहीं चल पाती है जबकि सारी प्राइवेट गाड़ियों की स्पीड 120 किलोमीटर प्रति घंटा हैं.

2:- दिल्ली में पेनिक बटन के नाम पर करोडो रूपया का घोटाला हो रहा हैं और अब इसका नाम बदल कर व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस रख कर टैक्सी बसों वाले से 16 हजार रुपये प्रति गाडी दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग द्वारा बनाये गए पेनल में प्राइवेट कम्पनी द्वारा लिया जा रहा हैं. जिसमे पेनिक बटन दबाने से कुछ नहीं होता जबकि ये महिलाओ की सुरक्षा के लिए टैक्सी बसों में लगाया जाता हैं, ये एक तरह से मात्र 5 रुपये का प्लास्टिक का बटन हैं जिसकी कीमत हमें 16 हजार से भी ज्यादा देनी पडती हैं.

3:- कमिशन फॉर एयर क्वालिटी मेनेजमेंट द्वारा बी एस 3/4 डीजल पेट्रोल की टैक्सी बसों को प्रदूषण की आड़ में हर साल बंद करा कर हम गरीब टैक्सी बसों के चालक / मालिकों से 20 हजार का जुर्माना वसूल किया जाता रहा हैं. जबकि प्रदूषण के दुसरे कारण जैसे कंस्ट्रक्शन की धुल मिट्टी और पराली जलाने पर कोई ठोस कदम नहीं उठाये जाते.

4:- इसी तरह प्रदूषण की आड़ में डीजल गाड़ियों को 10 साल में और पेट्रोल गाड़ियों को स्क्रीप (कूड़ा) बनाया जा रहा हैं.

5:- दिल्ली में पंजीकृत सभी व्यवसायिक वाहनों से नाजयाज एमसीडी टोल टैक्स वसूला जा रहा हैं. **आप 2024 के चुनाव को पर्वकी तरह बता रहें हैं.** हम आपसे ये जानना चाहते हैं की गर्मियों में तपती धूप में लाइनों में लग कर हम सांसदों को चुनते हैं जिससे बाद में सरकार बनाकर ये सब एयर कंडीशन ऑफिस में बैठ कर हमसे मिलते तक नहीं हैं और अगर किसी कारण से मिल भी गए तो ये हमारी मांगो को कार्यन्वित नहीं करते बल्कि सुप्रीम कोर्ट जाने की सलाह देते हैं, अगर हमें अपने सारे काम सुप्रीम कोर्ट से ही कराने हैं तो **हमें लाइन में लग कर चुनाव में वोट देने की क्या जरूरत हैं ?**

हम 2024 के चुनाव में वोट क्यों डाले क्या हम वोट करें तो आगे 5 सालो में ये सरकार और चुने सांसद हमारा काम करेंगे या हमें मिलने का समय देंगे इसकी गारंटी कौन लेगा? हम इस बारे में एक बार आप से मिलकर दिल्ली के टैक्सी बस मालिक / चालक फैसला करना चाहते है. क्योंकि दिल्ली एनसीआर के टैक्सी / बस मालिकों / चालकों में बहुत रोष हैं. *इसलिए आपसे विनती हैं की हमारे एक प्रतिनिधि मण्डल को मिलने का जल्द से जल्द समय दिया जाए।

ओमनी फाउंडेशन और परिवहन विशेष का साझा प्रयास:- सड़क सुरक्षा और जाम मुक्त सड़कें

आज की बहस का विषय :
लेन ड्राइविंग का पालन क्यों नहीं किया गया? अंकुर शरण

परिवहन विशेष न्यूज

अपने इनपुट साझा करें. कृपया विशिष्ट बनें और इस विषय पर बने रहें क्योंकि हमें सड़क सुरक्षा परिप्रेक्ष्य और दुर्घटना मुक्त शहर बनाने पर बेहतर समझ और कार्रवाई उन्मुख कार्य के लिए इनपुट लेने की आवश्यकता है।

ट्रैफिक जाम के और भी कारण हैं और ये हैं कौशल सह व्यवहार संबंधी लक्षण

प्रोफेसर शिव कुमार :-

1. क्योंकि पुलिस कभी भी लेन का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों को सबक नहीं सिखाती।

2. कम से कम हरियाणा में इसे वास्तविक अर्थों में कभी लागू ही नहीं किया गया

3. महंगी गाड़ियों पर सवार लोग कभी भी छोटी गाड़ियों का पीछा करना पसंद नहीं करते और इसलिए आगे निकलने की होड़ में सख्त कार्रवाई के अभाव में छूट लेते हैं।

ऐसे कई कारण हैं जिनकी वजह से भारत में लेन ड्राइविंग का सख्ती से पालन नहीं किया जा सकता है:

1. प्रवर्तन का अभाव: कुछ स्थानों पर यातायात कानूनों का कार्यान्वयन सीमित हो सकता है, जिससे लेन नियमों का पालन न करने पर परिणामों की कमी हो सकती है, लेन नियमों का पालन नहीं करना.

2. भीड़भाड़ वाली सड़कें*: भारत की सड़कें अत्यधिक भीड़भाड़ वाली हो सकती हैं, खासकर शहरी इलाकों में, जिससे लेन अनुशासन का पालन करना मुश्किल हो सकता है।

3. *सांस्कृतिक मानदंड*: कुछ मामलों में, ऐसे सांस्कृतिक दृष्टिकोण हो सकते हैं जो सख्त लेन नियमों का पालन करने के बजाय सड़क पर मुखरता को प्राथमिकता देते हैं।

4. *बुनियादी ढाँचे की चुनौतियाँ*: कुछ सड़कें अच्छी तरह से डिज़ाइन या रखरखाव नहीं की जा सकती हैं, जिससे ड्राइवरों के लिए लेन के भीतर रहना मुश्किल हो जाता है।

5. *सीमित जागरूकता*: सभी ड्राइवर लेन ड्राइविंग के महत्व से अवगत नहीं हो सकते हैं या उन्हें इस विषय पर पर्याप्त शिक्षा नहीं मिली होगी।

सड़क के बुनियादी ढांचे में सुधार, यातायात कानूनों के कार्यान्वयन को बढ़ाने और लेन ड्राइविंग के लाभों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के प्रयास समय के साथ लेन नियमों के अधिक पालन को प्रोत्साहित करने में मदद कर सकते हैं। जहां तक हमारे फाउंडेशन के प्रयासों का सवाल है, हमने अनपढ़ भारी वाहन, ट्रक, ट्रैक्टर चालकों को लेन ड्राइविंग के बारे में शिक्षित करने के लिए रिफ्लेक्टर टेप लगाने और साइकिल रैलियां (मुख्य रूप से मौज-मस्ती के लिए आयोजित) करने में कभी समय नहीं बिताया।

अंकुर शरण **क्या हम ? एक मोटे अनुमान के अनुसार, 75 से 80% ड्राइवर कम से कम लेन ड्राइविंग का पालन करते हैं।** बताए ?

संजय चतुर्वेदी:- मेरा मानना है कि ऐसा सिर्फ इसलिए है क्योंकि लोग स्व-नियमित नहीं हैं। 30 की गति से चलने वाली बाइक को सबसे दाहिनी लेन में चलाते रहें जो आदर्श रूप से तेज गति से चलने वाले वाहनों के लिए होती है। कारों को बायीं ओर से ओवरटेक करने के लिए मजबूर किया जाता है क्योंकि दायीं ओर से आगे निकलने के लिए कोई रास्ता नहीं देता है। कम से कम फ़रीदाबाद में मूल भावना पूरी तरह से नदारद है। दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा भी अपवाद नहीं हैं

अंकुर शरण:- विशेष रूप से वामपंथियों द्वारा यातायात संकेतों की बड़े पैमाने पर उपेक्षा के कारण यातायात की भीड़ बनी रहती है। ड्राइवर, अधीर और लेन बदलने के कारण समस्या को बढ़ा देते हैं, जबकि सुपर बाइकर्स और बड़े वाहनों के ड्राइवर अराजकता को बढ़ाते हैं। इस तरह के व्यवहार अव्यवस्था में योगदान करते हैं और सुचारू यातायात प्रवाह को बाधित करते हैं, जिससे समस्या बनी रहती है। हम इन मूल कारण विश्लेषण की पहचान करने का अनुरोध करते हैं और हमारे यातायात अधिकारी कुछ लेन परिवर्तन प्रतिबंध लगाते हैं और निगरानी शुरू करते हैं। **प्रवर्तन लागू होने तक लोगों को कम से कम परेशानी होती है।** कल गुरूग्राम से आते समय घाटा मोड़ से पारस तक अनावश्यक जाम 15-20 मिनट लग गया सिर्फ बिग बॉयज के कारण साइड लेन पर गाड़ियाँ खड़ी हैं और कुछ गलत तरीके से वापस आ रही हैं। **गलती किसकी है ?** दैनिक यात्री जो बिना किसी कारण के यातायात अव्यवस्था के कारण वास्तव में परेशान हैं। प्रवर्तन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, वर्दी में अधिकारियों की उपस्थिति लेन ड्राइविंग के लिए पर्याप्त है।

डॉक्टर पुनिता हसीजा :- देखा गया है कि भले ही कार चालक बाएं या दाएं मुड़ने के लिए इंडिकेटर दे रहा हो ;;;; सीधे जाने वाले दुपहिया और तिपहिया वाहन संकेत को नजरअंदाज कर आगे निकलने की कोशिश करेंगे

सिमरन फ्लोटेक:- नियमित आधार पर अवश्य, क्योंकी यहाँ सब ढीठ है. एक बार में नहीं मानेंगे. वास्तव में उन्हें दंडित भी किया जाना चाहिए, और इसमें शामिल व्यक्तियों की वेतन लागत सहित इन खर्चों को चलाने की सभी लागतें चूककर्ताओं से वसूल की जानी चाहिए।

अंकुर शरण:- यह मानवीय प्रवृत्ति है, एक अवज्ञा करेगा - बहुमत इस प्रवृत्ति का अनुसरण करेगा। पहले वाले को दंडित करने पर पीछे वाले स्वतः रुक जाएंगे और नियमानुसार चलेंगे।

रोड रेज और दुर्घटनाओं का प्रमुख कारण: लेन ड्राइविंग का पालन न करना

परिवहन विशेष न्यूज

रोड सेफ्टी ओमनी फाउंडेशन द्वारा हाल ही में कराए गए एक सर्वेक्षण में एक चिंताजनक प्रवृत्ति पर प्रकाश डाला गया: अधिकांश उत्तरदाताओं ने सड़कों पर दुर्घटनाओं का प्रमुख कारण लेन ड्राइविंग का पालन न करना बताया। यह रहस्योद्घाटन निराशाजनक परिणामों के साथ भारत में सड़क सुरक्षा को परेशान करने वाले एक महत्वपूर्ण मुद्दे को रेखांकित करता है। फाउंडेशन के सदस्यों ने इस मामले में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान की।

एक सदस्य ने ड्राइवरों के बीच शिक्षा की कमी की ओर इशारा किया, खासकर लेन अनुशासन के संबंध में।

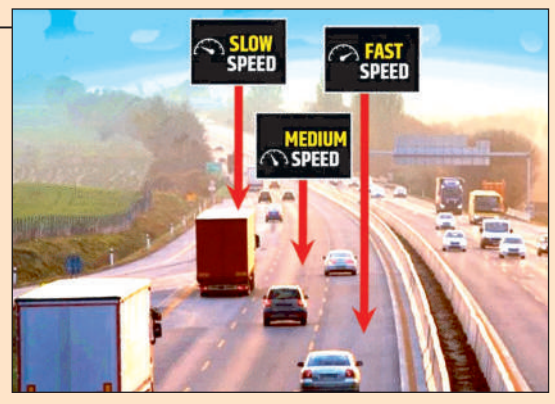

एक अन्य ने कार्यान्वयन की विफलता पर प्रकाश डाला, खासकर हरियाणा जैसे क्षेत्रों में। इसके अलावा, कुछ ड्राइवरों में, खासकर ऊंची कीमत वाले वाहनों में, आगे निकलने की होड़ में लेन नियमों का उल्लंघन करने की प्रवृत्ति प्रचलित है, जिससे सड़कों पर अराजक स्थिति पैदा हो जाती है। इस समस्या के मूल कारण बहुआयामी हैं। यातायात कानूनों को लागू करने में कमी, भीड़भाड़ वाली सड़कें, लेन नियमों के पालन पर दृढ़ता के पक्ष में सांस्कृतिक मानदंड, बुनियादी ढांचे की चुनौतियां और सीमित जागरूकता सभी इस मुद्दे में योगदान करते हैं।

सड़क के बुनियादी ढांचे में सुधार, प्रवर्तन को बढ़ाना और जागरूकता बढ़ाने सहित इन कारकों को संबोधित करने के प्रयास, लेन अनुशासन को बढ़ावा देने और दुर्घटनाओं को कम करने के लिए आवश्यक हैं। हालाँकि, ऐसा प्रतीत होता है कि फाउंडेशन के प्रयासों ने ड्राइवरों, विशेष रूप से भारी वाहनों का संचालन करने वालों को सीधे तौर पर लेन ड्राइविंग के बारे में शिक्षित करने के बजाय परिधीय गतिविधियों जैसे रिफ्लेक्टर टेप लगाने और साइकिल रैलियों पर अधिक ध्यान केंद्रित किया है। यह निरीक्षण मुख्य मुद्दे से निपटने में मौजूदा पहलों की प्रभावशीलता पर सवाल उठाता है।

इसके अलावा, ख़राब प्रबंधन से स्थिति और भी गंभीर हो जाती है, विशेषकर फ़रीदाबाद से गुरुग्राम रोड जैसे भारी यात्रा वाले मार्गों पर। टैग सिस्टम लागू किए बिना टोल संग्रहण जैसे मुद्दे अनावश्यक देरी का कारण बनते हैं, जिससे यात्रियों को बर्बाद हुए समय की भरपाई के लिए तेज गति और आक्रामक ओवरटेकिंग जैसे जोखिम भरे व्यवहार का सहारा लेना पड़ता है।

इन चुनौतियों से निपटने के लिए समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता है। ट्रैफिक पुलिस को लेन नियमों को लागू करने को प्राथमिकता देनी चाहिए और ज़ेबरा क्रॉसिंग पर पार्किंग, पीली बत्ती चलाना, दोपहिया वाहनों पर ट्रिपल सवारी और बिना हेलमेट के गाड़ी चलाने जैसे उल्लंघनों पर कार्रवाई करनी चाहिए।

इसके अतिरिक्त, शुरू से ही लेन अनुशासन के महत्व को स्थापित करने के लिए व्यापक ड्राइवर शिक्षा कार्यक्रमों की आवश्यकता है। लेन ड्राइविंग नियमों का पालन करने में विफलता भारत में सड़क सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण खतरा पैदा करती है, जिसके परिणामस्वरूप टाले जा सकने वाली दुर्घटनाएँ और सड़क क्रोध होते हैं। इस समस्या को कम करने के लिए, जिम्मेदार ड्राइविंग की संस्कृति को बढ़ावा देने और सभी के लिए सुरक्षित सड़कें सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों, संगठनों और व्यक्तियों के ठोस प्रयास आवश्यक हैं।

डॉ. अंकुर शरण
नेशनल चीफ प्लानिंग एंड ट्रांसपोर्ट ऑफिसर
रोड सेफ्टी ओमनी फाउंडेशन (रजि.)

दिल्ली एनसीआर की जनता से जनता का ही निवेदन

एडवोकेट बीएस यादव,
ओमनी फाउंडेशन

सभी दुपहियां एवं चौपहिया वाहनों के स्वामियों से निवेदन है कि आप सभी मिलकर एन. जी. टी. के द्वारा 10 साल एवं 15 साल के लिए हम सभी पर जो नियम लगाए जा रहे हैं वे आम जनता के खिलाफ हैं। अतः उनको वापस लेना जरूरी है। क्योंकि यह नियम केवल व्यवसायिक वाहनों के लिए तो ठीक है परन्तु निजी वाहनों के लिए बिल्कुल भी लागू नहीं होने चाहिये। हम सभी भलीभांति जानते हैं कि निजी वाहन इतने समय में कुछ ज्यादा नही चल पाते हैं। अति आवश्यक होने पर ही ये सडक पर निकलते हैं। सभी भाई परिवार की सुविधा के लिए ही वाहन खरीदते हैं ताकि बसों एवं ट्रेनों की भीड़ से बचा जा सके एवं इनकी मैनटेन्स का भी सभी भाई बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं। अपने शरीर से भी ज्यादा वाहन को मैन्टेन रखते हैं। जिस तरह हमारे शरीर का यदि कोई अंग बीमार हो जाता है तो उसका इलाज कराकर उसको सही करा लिया जाता है लेकिन एक अंग के ऊपर पूरे शरीर को ही नही बदला जाता है, ठीक उसी प्रकार वाहन का भी वही पार्ट बदलकर उसे भी ठीक करा लिया जाता है। अतः वाहन को कन्डम घोषित करना हमारे ऊपर अन्याय है। बडी मुश्किल से एक एक पैसा जोडकर हम अपने परिवार के लिए यह सुविधा कर पाते हैं। लेकिन एन.जी.टी. के लोग कुछ घंटों की मीटिंग में ही हमारी फैमिली को इस सुविधा से वंचित कर देते हैं यह हम सभी के लिए बहुत ही बड़ा अन्याय है एवं अन्याय के उपर लडना हमारा अधिकार है। लेकिन हम सब चुप रहकर इस अन्याय के विरुद्ध आवाज नही उठाते हैं। अब हम सभी को एकता के सूत्र में बंधकर इसके विरुद्ध आवाज उठानी चाहिए ताकि सरकार की समझ में आ जाए कि हम लोग अब किसी भी ऐसे अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाने के लिए एकता के सूत्र में बंधकर सरकार के अन्यायपूर्ण नियमों का विरोध करेंगे एवं सरकार को ऐसे नियम वापस लेने के लिए बाध्य कर देंगे। धन्यवाद।

सभी भाईयों से सविनय निवेदन है आम जनता की आवाज सरकार तक पहुंच जाए एवं सरकार को ऐसे नियम वापिस लेने के लिए बाध्य होना पडे।

निषादराज जयंती पर विशेष : "कभी - कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़ें, जाना था गंगा पार, प्रभु केवट की नाव चढ़े"

एड्वोकेट धर्मेंद्र निषाद

सभी को मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के अनन्य मित्र व भक्त निषाद राज़ जयंती पर हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई

मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान प्रभु श्री राम के प्रिय सखा महाराज गुहराज निषादराज की जयंती पर केवट समाज द्वारा बड़े ही भव्य रूप से शोभा यात्रा निकाली जाती है तथा प्रसाद वितरण किया जाता है।

इस अवसर पर धर्मेन्द्र निषाद एडवोकेट ने समस्त देशबासियों को मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के अनन्य मित्र व भक्त निषाद राज़ जयंती पर हार्दिक शुभकामनाएं देते हुये अपने वक्तव्य में बताया कि कभी - कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़ें, जाना था गंगा पार, प्रभु केवट की नाव चढ़े। केवट प्रभु श्री राम का अनन्य भक्त थे। यह दिन महाकाव्य रामायण में वन प्रमुख को समर्पित है। जिन्होंने भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण को निर्वासन के दौरान आश्रय दिया और उन्हें नदी पार करने में मदद की। निषादराज ने वन के तरीकों को अपनाने में भगवान प्रभु श्री राम की मदद की। अयोध्या के राजकुमार

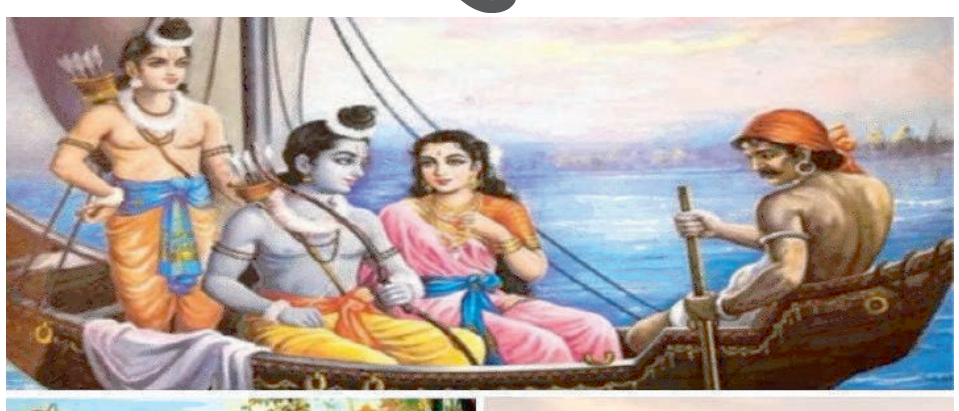

केवट जैसे सामान्यजन का निहोरा कर रहे हैं। यह समाज की व्यवस्था की अद्भुत घटना है। राम भक्त केवट चाहते है कि वह अयोध्या के राजकुमार को छुए। उनका सान्निध्य प्राप्त करें। उनके साथ नाव में बैठकर अपना खोया हुआ सामाजिक अधिकार प्राप्त करें। अपने संपूर्ण जीवन की मजूरी का फल पा जाए। प्रभु श्री राम ने केवट से नाव मांगी, वह कहने लगे - मैंने प्रभु आप का मर्म जान लिया। आप के चरण कमलों की धूल के लिए सब लोग कहते हैं, कि वह मनुष्य बना देने वाली कोई जड़ी है। प्रभु पहले आप पांव धुलवाओ, फिर नाव पर चढ़िए। उनके कहने पर प्रभु राम वह सब करते हैं, जैसा केवट चाहते थे। उसके श्रम को पूरा मान-सम्मान देते हैं। भक्त केवट राम राज्य का प्रथम नागरिक बन जाते है।

श्री धर्मेन्द्र ने आगे कहा कि निषाद समाज आज भी इनकी पूजा करते है। वनवास के बाद श्रीराम ने अपनी पहली रात अपने मित्र निषादराज के यहां बिताई। इसलिये इतिहास की यत्नपूर्वक रक्षा करनी चाहिए। धन तो आता है और चला जाता है, धन से हीन होने पर कुछ नष्ट नही होता किंतु इतिहास और अपना प्राचीनतम गौरव नष्ट होने पर उस समाज का विनाश निश्चित है। निषाद व सिन्धुघाटी की सभ्यता विश्व में सबसे प्रमुख तीन सभ्यताओं को माना जाता है। प्रभु राम त्रेता युग की संपूर्ण समाज व्यवस्था के केंद्र में हैं, इसे सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। उसके स्थान को समाज में ऊंचा करते हैं। राम की संघर्ष और विजय यात्रा में उसके दाय को बड़प्पन देते हैं। त्रेता के संपूर्ण समाज में केवट की प्रतिष्ठा करते हैं। इसी विचार के साथ एक वार पुनः समस्त देशबासियों को मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के अनन्य मित्र व भक्त निषाद राज़ जयंती पर हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई।

क्यों देवी गंगा ने अपने 7 पुत्रों को नदी में बहाया था? जानिए रहस्य

हर व्यक्ति के जीवन में मां ही तो वह एकमात्र अस्तित्व है, जो हर परिस्थिति में संतान को समझने, सुरक्षित रखने और साथ खड़े होने का भरोसा देती है. वो अपने बच्चों के लिए काल से भी लड़ जाती है. हिंदू धर्म में गंगा नदी को मां की उपाधि दी गई है. लेकिन महाभारत के अनुसार मां गंगा ने अपने ही 7 पुत्रों को मौत के मुंह में धकेल दिया था. आइए जानते है मां गंगा ने आखिर क्यों अपने 7 पुत्रों को नदी में बहाया था- महाभारत के आदि पर्व के अनुसार, एक बार पृथु पुत्र जिन्हें वसु कहा जाता था, वो अपनी पत्नियों के साथ मेरु पर्वत पर घूम रहे थे. वहां वशिष्ठ ऋषि का आश्रम भी था. वहां नंदिनी नाम की गाय थी. द्यो नामक वसु ने अन्य वसुओं के साथ मिलकर अपनी पत्नी के लिए उस गाय का हरण कर लिया. जब महर्षि वशिष्ठ को पता चला तो उन्होंने क्रोधित होकर सभी वसुओं को मनुष्य योनि में जन्म लेने का श्राप दे दिया. वसुओं द्वारा क्षमा मांगने पर ऋषि ने कहा कि तुम सभी वसुओं को तो शीघ्र ही मनुष्य योनि से मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन इस द्यौ नामक वसु को अपने कर्म भोगने के लिए बहुत दिनों तक पृथ्वीलोक में रहना पड़ेगा. इस श्राप की बात जब वसुओं ने गंगा को बताई तो गंगा ने कहा कि 'मैं तुम सभी को अपने गर्भ में धारण करूंगी और तत्काल मनुष्य योनि से मुक्त कर दूंगी'. गंगा ने ऐसा ही किया. वशिष्ठ ऋषि के श्राप के कारण भीष्म को पृथ्वी पर रहकर दुख भोगने पड़े. जब आठवें पुत्र को नदी में बहाने से रोक लिया शांतनु ने जब गंगा ने शांतनु से विवाह किया था तो गंगा ने राजा के सामने एक शर्त रखी थी कि अगर जीवन में राजा शांतनु ने कभी भी गंगा को किसी काम को करने से रोका या टोका तो, वो तुंरत राजा शांतनु को छोड़कर चली जाएगी. 7 पुत्रों को बहा देने के बाद शांतनु ने आठवें पुत्र को बहाने से गंगा को रोक लिया. जिसके बाद गंगा ने शर्त का पालन करने पर शांतनु को छोड़ दिया. देवी गंगा आठवें पुत्र को लेकर अदृश्य हो गई. जब लौट आई गंगा और आठवें पुत्र का नाम रखा गया भीष्म एक दिन गंगा नदी के तट पर घूम रहे थे. वहां उन्होंने देखा कि गंगा में बहुत थोड़ा जल रह गया है और वह भी प्रवाहित नहीं हो रहा है. इस रहस्य का पता लगाने जब शांतनु आगे गए तो उन्होंने देखा कि एक सुंदर व दिव्य युवक अस्त्रों का अभ्यास कर रहा है और उसने अपने बाणों के प्रभाव से गंगा की धारा रोक दी है. यह दृश्य देखकर शांतनु को बड़ा आश्चर्य हुआ। तभी वहां शांतनु की पत्नी गंगा प्रकट हुई और उन्होंने बताया कि यह युवक आपका आठवां पुत्र है. उस युवक की बुद्धि और कौशल देखकर उसका नाम देवव्रत से 'भीष्म' रखा गया. अपने पुर्नजन्म के पाप के कारण भीष्म को जीवन भर दुख सहना पड़ा अर्थात उनका पूरा ही जीवन श्रापित था.

समर सीजन में ड्रैगन फ्रूट खाने से हेल्थ को मिलते हैं गजब के फायदे

दिव्यांशी भदौरिया

ड्रैगन फ्रूट एक स्वादिष्ट और पौष्टिक फल है जो कई संभावित स्वास्थ्य लाभ प्रदान करता है।यह फ्रूट में पोषक तत्वों का खजाना है अगर इसे सुपर फूड कहे तो गलत नहीं। ड्रैगन फ्रूट को कच्चा खाते है, लेकिम आप चाहे तो इससे कई तरह के व्यंजन बना सकते है। जानिए ड्रैगन फ्रूट खाने के कुछ स्वास्थ्य लाभ।

ड्रैगन फ्रूट को पिताया भी कहा जाता है और यह एक उष्णकटिबंधीय फल है जो अमेरिका के मूल निवासी कई प्रकार के कैक्टस से प्राप्त होता है। यह अपनी चमकीली गुलाबी या पीली सतह और काले बीज के स्पष्ट, सफेद-मांसल आंतरिक भाग द्वारा पहचाना जाता है। ड्रैगन फ्रूट न केवल शारीरिक रूप से बेहतर है, बल्कि संतुलित आहार के हिस्से के रूप में सेवन करने पर इसके कई संभावित स्वास्थ्य लाभ भी हैं। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के अनुसार, लाल ड्रैगन फ्रूट के गूदे में बेलाटिन होता है, जो कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल और अन्य स्वास्थ्य जोखिम कारक को काफी कम करता है।

जानिए ड्रैगन फ्रूट खाने के कुछ स्वास्थ्य लाभ

पोषक तत्वों से भरपूर

ड्रैगन फ्रूट में कैलोरी कम होती है लेकिन यह आवश्यक पोषक तत्वों से भरपूर होता है। यह विटामिन सी का एक अच्छा स्रोत है, जो प्रति 100 ग्राम फल में 9 मिलीग्राम तक प्रदान करता है, जो अनुशंसित दैनिक सेवन का लगभग 10-20% है। ड्रैगन फ्रूट में बीटालेन और फ्लेवोनोइड जैसे विभिन्न एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जो शरीर में हानिकारक मुक्त कणों को बेअसर करने और ऑक्सीडेटिव तनाव को कम करने में मदद करते हैं। इसमें उच्च मात्रा में आहार फाइबर होता है, जो पाचन स्वास्थ्य का समर्थन करता है, तृप्ति को बढ़ावा देता है और शुगर के लेवल को नियंत्रित करने में मदद करता है।

इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करता है

ड्रैगन फ्रूट में विटामिन सी की उच्च मात्रा वाइट ब्लड सेल्स के उत्पादन को उत्तेजित करके, संक्रमण और बीमारियों से लड़ने की शरीर की क्षमता को बढ़ाकर प्रतिरक्षा समारोह का समर्थन करने में मदद करती है।

पाचन स्वास्थ्य को इम्प्रूव करता है

ड्रैगन फ्रूट में मौजूद फाइबर सामग्री मल में मात्रा जोड़कर, नियमित मल त्याग को बढ़ावा देकर और कब्ज को रोककर पाचन में सहायता करती है। इसके अलावा ड्रैगन फ्रूट के प्रीबायोटिक गुण लाभकारी आंत बैक्टीरिया को पोषण देने में मदद कर सकते हैं, जिससे गट हेल्थ को समर्थन मिलता है।

हार्ट हेल्थ को बेहतर करता है

ड्रैगन फ्रूट में एंटीऑक्सिडेंट और फाइबर जैसे हार्ट -हेल्थ पोषक तत्व होते हैं, जो कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करके, रक्तचाप में सुधार और स्वस्थ रक्त वाहिका कार्य को बढ़ावा देकर हृदय रोग के जोखिम को कम करने में मदद कर सकते हैं।

हाइड्रेशन प्राप्त होता है

ड्रैगन फ्रूट में पानी की मात्रा अधिक होती है, जो इसे हाइड्रेटिंग फल का विकल्प बनाता है, खासकर गर्म जलवायु में या शारीरिक गतिविधि के दौरान। अच्छी सेहत और कल्याण के लिए हाइड्रेटेड रहना आवश्यक है।

गुड फॉर स्किन हेल्थ

ड्रैगन फ्रूट में विटामिन सी और एंटीऑक्सिडेंट कोलेजन उत्पादन को बढ़ावा देने, त्वचा की लचीलेपन में सुधार करने और यूवी विकिरण और पर्यावरण प्रदूषकों के कारण होने वाली समय से पहले उम्र बढ़ने से बचाने में मदद कर सकते हैं।

वजन प्रबंधन में सहायता मिलती

अपनी कम कैलोरी और उच्च फाइबर सामग्री के कारण, ड्रैगन फ्रूट वजन घटाने या वजन प्रबंधन आहार के लिए एक सबसे बढ़िया और पौष्टिक अतिरिक्त हो सकता है। फाइबर समग्र कैलोरी सेवन को कम करके तृप्ति की भावना को बढ़ावा देने में मदद करता है।

बच्चों का नाम सावधानी से रखें आखिर क्यों?

सनातन धर्म में सोलह संस्कार बताए गए हैं। इनमें से नामकरण संस्कार को बेहद महत्वपूर्ण संस्कार माना गया है। नाम किसी भी व्यक्ति के लिए पूरे जीवन की पहचान होता है। ज्योतिष के अनुसार, नाम का प्रभाव व्यक्ति के स्वभाव और भाग्य पर भी पड़ता है। इसलिए नाम रखने से पहले कुछ बातों पर विचार जरूर कर लें। तो चलिए जानते हैं कि बच्चे का नाम रखने से पहले किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए-:

नाम के अर्थ का रखें ध्यान-: आज के समय में लोग चाहते हैं कि उनके बच्चे का नाम कुछ हटकर नया हो। इसलिए जो नाम वे सीरियल या फिल्मों में देखते हैं, वही नाम वे अपने बच्चो का रख देते हैं, लेकिन बच्चे का नाम रखने से पहले उसका अर्थ जानना बेहद जरूरी होता है। अपने बच्चे के लिए एक ऐसा नाम चुनें जिसका अर्थ अच्छा व सकारात्मक हो, क्योंकि बच्चे के नाम का प्रभाव उसके पूरे व्यक्तित्व पर पड़ता है।।

नामकरण के लिए सही दिन का चुनाव करें-: नामकरण के लिए चुनें सही दिन-

बच्चे के जन्म के बाद ग्यारहवें या सोलहवें दिन नामकरण संस्कार किया जाता है लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि उस दिन संक्रांति, पूर्णिमा, अमावस्या, रिक्ता तिथि नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा यदि गंडमूल में बच्चे का जन्म हुआ है तो पूरे सत्ताइस दिनों के बाद ज्योतिष की सलाह से ही नामकरण संस्कार करवाना चाहिए। ध्यान रहे शुभ मुहूर्त में ही नामकरण संस्कार करें।

नामांक, मूलांक, भाग्यंक मित्र हो व राशि/नक्षत्र से भी हो तालमेल-: यदि बच्चे के नाम का नामांक उसके मूलांक व भाग्यंक के अनुकूल हो अर्थात नामांक, मूलांक और भाग्यांक की आपस में मित्रता हो और साथ- साथ आपकी जन्म राशि व जन्म नक्षत्र का भी आपके नामांक से

तालमेल हो तो इस तरह का नाम आपके बच्चे के जीवन में उन्नति प्रदान करने वाला होता है।।

अलग-अलग नाम नहीं रखने चाहिए-: अक्सर देखने में आता है कि लोग प्यार से बच्चे को अलग-अलग नामों से पुकारते हैं। घर का अलग नाम होता है तो वहीं बाहर का नाम अलग होता है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। घर और बाहर दोनों के लिए एक ही नाम रखना चाहिए। अलग-अलग नाम होने पर बच्चे को कई बार परेशानी उठानी पड़ती है।

अर्थहीन व हल्की ऊर्जा वाले नाम ना रखें-: कई बार प्यार से बच्चे को अर्थहिन नामो से पुकारा जाता है, जैसे पप्पू, गप्पू, चिंटू, मिंटू, चुन्नू, मुन्नू, रॉकी, जॉकी, रिंकी, पिंकी आदि, इसका बच्चे पर बहुत गलत प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के तौर पर यदि आप अपने बच्चे को बार-बार पप्पू कहेंगे तो बाहर के लोग भी उसे धीरे-धीरे पप्पू कहने लगेंगे। और यह पप्पू नाम का वाइब्रेशन उस बच्चे पर काफी नेगेटिव प्रभाव छोड़ेगा। बच्चा जब बड़ा होगा तो भी उसकी हरकतें अनमैच्योर बच्चें जैसी ही रहेगी व बच्चा मेच्योर नहीं हो पाएगा। ऐसे अर्थ हीन नाम बच्चों की सफलता में भी बाधक होते हैं। अतः ध्यान रहे कभी प्यार से भी अपने बच्चों को हल्की ऊर्जा वाले अर्थ हीन नामों से ना पुकारें।।

नयंश	ईश्वर का सबसे खूबसूरत निर्माण, अनोखा
नित्यम	लगातार, स्थिरता
नैतविक	नीतियों को मानाने वाला, अनुशासित
नक्षत्र	सितारा, चमक
महिक	सुगंध, मन को अच्छा लगने वाला
मन्वित	मानवता, शक्ति
मितांश	मित्र, दोस्त
मणिक	रत्न, लाल मणि
मिहित	आनंद, उत्साह
मेधांश	बुद्धिमान, आत्मविश्वासी
मान	गर्व, सम्मान
मानस	आत्मा, बुद्धि, मनुष्य
मायुन	पानी का स्रोत, समृद्धि से भिन्न

वाइल्डलाइफ के शौकीन लोगों को करना चाहिए इन नेशनल पार्कों की करें सैर, एडवेंचर से भरपूर होगी ट्रिप

अनन्या मिश्रा

अगर आपको प्रकृति से प्यार है और जंगलों में जानवरों के अलावा हरे-भरे नजारे देखना चाहते हैं। तो आप भी आप भी भारत के प्रसिद्ध जंगलों को घूमने जा सकते हैं। आइए जानते हैं देश के फेमस जंगलों और इनकी खासियत के बारे में।

वैसे तो भारत में कई बड़े घने और ऊंचे जंगल पाए जाते हैं। जो देश को हरा-भरा और सुंदर बनाते हैं। देश के मिजोरम राज्य में सबसे ज्यादा जंगल है। वहीं मध्य प्रदेश में भी सबसे ज्यादा जंगल वाली भूमि है। देश के अलग-अलग राज्यों में जंगल है, जो पर्यटकों के घूमने के लिए खोले गए हैं। वहीं हाल ही में देश के प्रधानमंत्री मोदी असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में जंगल सफारी का लुत्फ उठाने के लिए पहुंचे थे। अगर आपको प्रकृति से प्यार है और जंगलों में जानवरों के अलावा हरे-भरे नजारे देखना चाहते हैं। तो यह आर्टिकल आपके लिए है।

आज इस आर्टिकल के जरिए हम आपको देश के सबसे सुंदर और फेमस जंगलों के बारे में बताने जा रहे हैं। ऐसे में आप भी आप भी भारत के प्रसिद्ध जंगलों को घूमने जा सकते हैं। आइए जानते हैं देश के फेमस जंगलों और इनकी खासियत के बारे में।

जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क

यह नेशनल पार्क भारत का सबसे मशहूर वाइल्ड लाइफ पार्क है। बता दें कि यह एशिया का पहला उद्यान है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में बाघों की कई प्रजातियां देखने को मिल जाएंगी। ऐसे में बारिश का मौसम छोड़कर यहां कभी भी जा सकते हैं। मार्च से मई महीने में यहां पर जाना सबसे बेहतर होगा।

काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान

यह राष्ट्रीय उद्यान विश्व में एक सींग वाले गैंडे के लिए काफी फेमस है। यह असम का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। असम में स्थित इस नेशनल पार्क में सेंट्रल कोहोरा रेंज है। यहां पर आप मिहिमुख क्षेत्र में हाथी की सवारी और जीप सफारी का आनंद ले सकते हैं। हाल ही में पीएम मोदी ने काजीरंगा नेशनल पार्क में जंगल सफारी की थी। ऐसे में आप भी प्राकृतिकता के बीच एडवेंचर ट्रिप का लुत्फ उठा सकते हैं।

सुंदरवन का जंगल

पश्चिम बंगाल में सुंदरवन का जंगल स्थित है। इसको भारत के सबसे बड़े और खतरनाक जंगल के रूप में जाना जाता है। भारत और बांग्लादेश दोनों में ही यह जंगल पड़ता है। गंगा नदी के डेल्टा पर यह जंगल स्थित है। आपको बता दें कि यह जंगल रॉयल बंगाल टाइगर के लिए जाना जाता है। यहां के खारे पानी में बहुत सारे मगरमच्छ हैं। इसी स्थान पर भारत की पवित्र नदियां गंगा, पद्मा, ब्रह्मपुत्र और मेघना आदि समुद्र में मिलती हैं।

कान्हा राष्ट्रीय उद्यान

आपको बता दें कि मध्य प्रदेश अपने जंगलों और राष्ट्रीय पार्क के लिए फेमस है। एमपी में एक ऐसा ही फेमस नेशनल पार्क है। जिसका नाम कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान को साल 1955 में नेशनल पार्क का दर्जा मिला था। इस पार्क में आपको विलुप्त हो चुकी बारहसिंघा की प्रजातियां देखने को मिल जाएंगी। यह नेशनल पार्क जबलपुर से 175 किमी दूर स्थित है।

रणथंबोर नेशनल पार्क

रणथंबोर नेशनल पार्क रावली और विंध्य की पहाड़ियों में फैला है। इस नेशनल पार्क में चीते, सांभर, बाघ, जंगली सूअर, चिंकारा, हिरण और तेंदुए की तमाम प्रजातियां पाई जाती हैं। इसके अलावा आप यहां पर पक्षियों की करीब 264 प्रजातियां देख सकते हैं। वहीं रणथंबोर नेशनल पार्क में जीप सफारी का लुत्फ उठाने के लिए अक्टूबर से लेकर जून तक के बीच जाना चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट से केजरीवाल सरकार को बड़ी राहत, दिल्ली जल बोर्ड मामले में प्रधान सचिव को जारी किए ये आदेश

परिवहन विशेष न्यूज

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) को नोटिस जारी किया है। यह नोटिस बकाए राशि के बारे में जानकारी मांगने के संबंध में है। वहीं मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने दिल्ली सरकार के प्रधान सचिव (वित्त) को धनराशि जारी करने के लिए कहा है। मामले में अगली सुनवाई 10 अप्रैल को होगी।

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को आप सरकार की उस याचिका पर दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) को नोटिस जारी किया है जिसमें पीने योग्य पानी की आपूर्ति के लिए जिम्मेदार निकाय को धन जारी नहीं करने का आरोप लगाया गया है।

मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने दिल्ली सरकार के प्रधान सचिव (वित्त) को धनराशि जारी करने के लिए कहा है। पीठ ने कहा कि वह जल उपयोगिता से बकाया धनराशि के बारे में जानना चाहती है।

याचिका पर अगली सुनवाई 10 अप्रैल को

सुप्रीम कोर्ट ने अब दिल्ली सरकार की याचिका पर आगे की सुनवाई 10 अप्रैल को तय की है। 1 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने प्रधान सचिव (वित्त) को उस याचिका पर नोटिस जारी किया था जिसमें आरोप लगाया गया था कि अधिकारी विधानसभा द्वारा बजटीय मंजूरी के बावजूद दिल्ली जल बोर्ड को धन जारी नहीं कर रहे हैं। दिल्ली सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी ने कहा था, ₹मेरे अधिकारी मेरी बात नहीं सुनते हैं। उन्होंने कहा था कि डीजेबी को 1,927 करोड़ रुपये अभी भी जारी नहीं किए गए हैं।₹

सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को दिया था आश्वासन

बता दें, केजरीवाल सरकार ने नौकरशाही और दिल्ली में सत्तारूढ़ आप सरकार से जुड़े ताजा विवाद के मुद्दे पर 20 मार्च को शीर्ष अदालत का रुख किया था। सीजेआई ने आप सरकार को आश्वासन दिया था कि वह 31 मार्च को समय सीमा समाप्त होने के बाद भी डीजेबी के लिए निर्धारित धनराशि जारी करने का आदेश दे सकते हैं।

दिल्ली जल बोर्ड के अनुबंध में ली गई रिश्वत का पैसा AAP को चुनावी फंड में गया, कोर्ट ने ED को दिए ये निर्देश

ईडी ने एक बयान में आरोप लगाया है कि एनकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को ठेका देने के बाद अरोड़ा ने नकद और बैंक खातों में रिश्वत ली और यह पैसा डीजेबी मामलों का प्रबंधन करने वाले विभिन्न लोगों को दिया जिनमें आप से जुड़े लोग भी शामिल थे।

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। दिल्ली जल बोर्ड घोटाले से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में अदालत ने ईडी के आरोपपत्र पर संज्ञान लिया। ईडी ने आरोपपत्र में दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) के एक पूर्व मुख्य अभियंता जगदीश अरोड़ा, ठेकेदार अनिल कुमार अग्रवाल, चार्टर्ड अकाउंटेंट तेजिंदर पाल सिंह समेत अन्य लोगों को आरोपित बनाया है।

राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश भूपिंदर सिंह के समक्ष कार्यवाही के दौरान, डीजेबी के पूर्व मुख्य अभियंता जगदीश अरोड़ा और ठेकेदार अनिल अग्रवाल को जेल अधिकारियों द्वारा अदालत के समक्ष पेश किया गया। वहीं, अदालत द्वारा जारी किए गए समन के अनुपालन में आरोपित तेजिंदर सिंह भी अदालत के सामने पेश हुए।

चौथे आरोपित एनबीसीसी के पूर्व महाप्रबंधक डीके मित्तल ने एक दिन के लिए व्यक्तिगत पेशी से छूट की मांग करते हुए आवेदन दायर किया था। अदालत ने ईडी को आरोपितों को आरोपपत्र की प्रति उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। अदालत ने दस्तावेजों की जांच के लिए मामले की सुनवाई 20 अप्रैल को तय की है।

चुनावी फंड के रूप में गया पैसा

ईडी ने अरोड़ा और अग्रवाल को गिरफ्तार किया था। वहीं, तजिंदर पाल सिंह, देवेंद्र कुमार मित्तल और मेसर्स एनकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के खिलाफ बिना गिरफ्तारी के आरोप पत्र दायर किया गया था। ईडी ने आरोप लगाया है कि डीजेबी द्वारा जारी एक अनुबंध में भ्रष्टाचार से उत्पन्न रिश्वत का पैसा आम आदमी पार्टी (आप) को चुनावी फंड के रूप में पारित किया गया था।

एजेंसी ने कहा है कि डीजेबी का ठेका अत्यधिक बढ़ी हुई दरों पर दिया गया था ताकि ठेकेदारों से रिश्वत वसूली जा सके। ईडी ने कहा 38 करोड़ रुपये के अनुबंध मूल्य के मुकाबले, अनुबंध पर केवल 17 करोड़ रुपये खर्च किए गए और शेष राशि विभिन्न फर्जी खर्चों की आड़ में निकाल ली गई।

पूछताछ के लिए केजरीवाल को बुलाया था

आरोप लगाया कि ऐसे फर्जी खर्च रिश्वत और चुनावी फंड के लिए दर्ज किए गए थे। ईडी ने इस मामले में पूछताछ के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी बुलाया था, लेकिन वह उसके सामने पेश नहीं हुए।

अदालत ने कहा कि रिकार्ड पर रखी गई सामग्री से ऐसा प्रतीत होता है कि सभी आरोपित व्यक्ति व कंपनी या तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपराध की आय छिपाने, कब्जे, अधिग्रहण, उपयोग और उसे बेदाग संपत्ति के रूप में पेश करने या दावा करने से संबंधित प्रक्रिया या गतिविधियों में शामिल पाए गए हैं।

जाली दस्तावेज जमा करके बोली हासिल की

कोर्ट ने कहा कि अदालत की राय में आरोपित व्यक्तियों के खिलाफ शिकायत में उल्लिखित आरोपों पर आगे बढ़ने के लिए रिकार्ड पर पर्याप्त सामग्री है। ईडी के मुताबिक जांच में पता चला कि मेसर्स एनकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने जाली दस्तावेज जमा करके बोली हासिल की। जगदीश कुमार अरोड़ा भी इस बात से अवगत हैं कि कंपनी निविदा की मंजूरी के लिए तकनीकी मानदंडों को पूरा नहीं करती है।

रिश्वत की रकम आप को भी दी गई

ईडी के एक बयान में आरोप लगाया गया है कि एनकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को ठेका देने के बाद अरोड़ा ने नकद और बैंक खातों में रिश्वत ली और यह पैसा डीजेबी मामलों का प्रबंधन करने वाले विभिन्न लोगों को दिया, जिनमें आप से जुड़े लोग भी शामिल थे। रिश्वत की रकम चुनावी फंड के तौर पर आप को भी दी गई।

केजरीवाल को वकीलों से कितनी बार मिलने की परमिशन? दिल्ली CM की याचिका पर 9 अप्रैल को आएगा फैसला

परिवहन विशेष न्यूज

तिहाड़ जेल में बंद अरविंद केजरीवाल की वकीलों से मिलने से जुड़ी याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया। अब दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट 9 अप्रैल को मुख्यमंत्री केजरीवाल की याचिका पर फैसला सुनाएगा। जेल मैनुअल के हिसाब से एक हफ्ते में उन्हें अभी दो बार वकीलों से मुलाकात की अनुमति है। बता दें कि अरविंद केजरीवाल अभी शराब घोटाले में न्यायिक हिरासत में जेल में हैं।

दिल्ली। तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की उस याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया, जिसमें उन्होंने अपने वकीलों से मुलाकात का समय हफ्ते में 2 बार से बढ़ाकर 5 बार करने का अनुरोध किया था। बता दें कि जेल मैनुअल के हिसाब से हफ्ते में उन्हें अभी दो बार वकीलों से मुलाकात की अनुमति है।

याचिका फैसला सुरक्षित

दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने मामले में सुनवाई करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया। अब कोर्ट 9 अप्रैल को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर फैसला सुनाएगा। इससे पहले दिल्ली की अदालत ने अरविंद केजरीवाल को जेल में इलेक्ट्रिक केतली, मेज, कुर्सी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया था।

24 घंटे CCTV निगरानी में सीएम

बता दें कि सीएम अरविंद केजरीवाल 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में बंद हैं। उनको 24 घंटे सीसीटीवी निगरानी में तिहाड़ के एक बैरक में रखा गया है। जेल में उन्हें घर का खाना देने की अनुमति है। इसके लिए घर से दिन व रात का खाना लेकर आने वाले लोगों के नाम भी जेल प्रशासन को उपलब्ध कराए गए हैं।

केजरीवाल तीसरी बार गए जेल

जिन व्यक्तियों के नाम उपलब्ध कराए गए हैं, केवल वही मुख्यमंत्री के लिए खाना लेकर आ सकते हैं। खास बात है कि अरविंद केजरीवाल को तीसरी बार तिहाड़ जेल ले जाया गया है। इससे पहले, उन्हें अन्ना हजारे के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन के दौरान और 2014 में मानहानि के मामले में जेल ले जाया गया था।

'बीजेपी ने किया शराब घोटाला, कई बड़े नेता शामिल', आप नेता संजय सिंह का बड़ा दावा

आम आदमी पार्टी के दिल्ली से राज्यसभा सांसद संजय सिंह दो दिन पहले Delhi Excise Policy Scam केस में जमानत पर रिहा हुए हैं। रिहाई के बाद से ही वह राजनीति में पूरी तरह से सक्रिय हो गए हैं। वह लगातार पार्टी की गतिविधियों में लिप्त हैं। शुक्रवार सुबह संजय सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बड़ा खुलासा किया है।

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें उन्होंने दावा किया है कि दिल्ली शराब घोटाला भाजपा ने किया है। इस घोटाले में भाजपा के कई बड़े नेता शामिल हैं।

उन्होंने ये भी दावा किया है कि केजरीवाल की गिरफ्तारी साजिश के तहत हुई है। संजय सिंह ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दाव किया है कि दिल्ली शराब घोटाले में जिन लोगों को आरोपियों के रूप में पकड़ा गया था, उन्होंने जब तक केजरीवाल का नाम नहीं लिया, ईडी ने उनके बयान को भरोसे लायक नहीं माना लेकिन जैसे ही उन्होंने अरविंद केजरीवाल का नाम ले लिया उस बयान को मान लिया गया।

उन लोगों के बयानों के आधार पर केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया। केजरीवाल ने सरकार बन चुके आरोपियों का नाम अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में लिया। पहला नाम संजय सिंह ने मगुंता रेड्डी का लिया और दूसरा नाम शरत रेड्डी का लिया।

दसवें बयान में आया केजरीवाल का नाम

सांसद संजय सिंह ने दावा किया, भाजपा नेता मगुंटा रेड्डी और उसके बेटे राघव मगुंटा इसमें शामिल हैं। इन्होंने दबाव में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बयान दिया। इनके नौ बयानों में कहीं कुछ नहीं था जबकि दसवें बयान में अरविंद केजरीवाल का नाम आ जाता है।

16 जुलाई को इन्होंने बयान दिया और 18 जुलाई को उसकी जमानत हो गई। इनकी फोटो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ है और इसी फोटो के साथ वह टीडीपी से सांसद का चुनाव लड़ रहा है। संजय सिंह ने आगे कहा, इनके बाद नाम आता है शरत रेड्डी का। इनके 12 बयान लिए गए। शुरुआती बयानों में यह कहते रहे कि केजरीवाल को नहीं जानते। छह महीने जेल में रहा तो टूट गया।

शरत रेड्डी को कहा घोटालेबाज और ले लिए 55 करोड़ रुपये

केजरीवाल के खिलाफ बयान दे दिया। उनकी जमानत भी हो गई। भाजपा शरत रेड्डी को शराब का घोटालेबाज कहती है। लेकिन उसी ने 55 करोड़ रुपए भाजपा को दिया।

21 मार्च को जब साबित हो गया कि शराब घोटाला भाजपा ने किया है। रात को केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया।

आखिरी में संजय सिंह ने कहा, केजरीवाल एकदम बेदाग है। उन्हें उनके अच्छे कामों की सजा दी जा रही है।भाजपा का नारा है जो जितना बड़ा भ्रष्टाचारी, उतना बड़ा पदाधिकारी।

जेल से रिहा होने के बाद गए मंदिर और गांधी समाधि

तिहाड़ जेल से रिहा होने के एक दिन बाद आप के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने बृहस्पतिवार को कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर में पूजा-अर्चना की और कहा कि उन्होंने भाजपा नीत केंद्र सरकार को सद्बुद्धि देने के लिए प्रार्थना की।

फिर उन्होंने राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि भी अर्पित की। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा, जिस तरह से दिल्ली और झारखंड के मुख्यमंत्रियों को जेल भेजा गया, वह देश में 'तानाशाही' की शुरुआत है।

संजय सिंह ने ये दावा भी किया

उन्होंने आगे कहा, 'वे अन्य मुख्यमंत्रियों को भी जेल भेजने की तैयारी कर रहे हैं। यह देश में लोकतंत्र और संविधान के लिए बहुत खतरनाक है और हमें इसके खिलाफ लड़ने की जरूरत है।'

उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासकों के खिलाफ लड़ाई लड़ी क्योंकि उस समय बोलने और रहने की आजादी नहीं थी। उन्होंने दावा किया कि आजादी के 77 साल बाद अब वही स्थिति पैदा हो गई है।

भाजपा ने उन्हें इस बार भी उत्तर पूर्वी दिल्ली से मैदान में उतारा है। लेकिन क्या मनोज जनता के भरोसे पर भी खरे उतरे हैं?

सांसद के रूप में कैसा रहा मनोज तिवारी का कार्यकाल? देखिए रिपोर्ट कार्ड

परिवहन विशेष न्यूज

दिल्ली में भाजपा ने सात में से 6 सीटों पर प्रत्याशी बदले हैं। केवल मनोज तिवारी को फिर से उनकी उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट से मैदान में उतारा गया है। सांसद के रूप में मनोज तिवारी पार्टी का भरोसा जीतने में तो कामयाब रहे लेकिन जनता के भरोसे पर वह कितने खरे उतरे हैं ये जानने के लिए पढ़ें उनका रिपोर्ट कार्ड।

नई दिल्ली। भाजपा ने इस बार लोकसभा चुनाव के लिए दिल्ली की सात सीटों में से 6 पर प्रत्याशी बदल दिए हैं। मौजूदा सांसदों में से केवल मनोज तिवारी को एक बार फिर से उनकी सीट पर टिकट दिया गया है। निश्चित ही वह पार्टी आलाकमान का भरोसा जीतने में कामयाब रहे हैं।

भाजपा ने उन्हें इस बार भी उत्तर पूर्वी दिल्ली से मैदान में उतारा है। लेकिन क्या मनोज जनता के भरोसे पर भी खरे उतरे हैं? जानिए सांसद के रूप में कैसा रहा उनका रिपोर्ट कार्ड। बता दें कि पिछले चुनाव में मनोज तिवारी ने उत्तर पूर्वी दिल्ली से कुल 7,87,799 मतों के साथ जीत दर्ज की थी।

विशेष उपलब्धियां

बतौर सांसद 2019 से 2024 तक के कार्यकाल में कई विशेष उपलब्धियां भी उनके खाते में रही हैं, जैसे, दिल्ली-सहारनपुर हाईवे का निर्माण शुरू कराया, मौजपुर से मजलिस पार्क तक मेट्रो विस्तार दिलाया एवं यमुना किनारे रिवर फ्रंट का निर्माण शुरू कराया।

इसके अलावा शास्त्री पार्क में कन्वेंशन सेंटर तैयार कराना, यमुना की स्वच्छता के लिए अमृत योजना से 1,210 करोड़ रुपये वजीराबाद में एसटीपी के लिए दिलवाना, बेहतर शिक्षा के लिए शाहदरा में केंद्रीय विद्यालय का निर्माण कराना, खजूरी खास में भी केंद्रीय विद्यालय की स्वीकृति दिलाना एवं उसके लिए भूमि का आवंटन कराना जैसी उपलब्धियां भी उन्होंने हासिल की हैं।

पांच बड़ी विफलताएं

लेकिन हालिया कार्यकाल में कई ऐसे मुद्दे भी रहे जिन पर आवश्यकता के अनुसार काम नहीं हो पाया। इनमें पांच बड़ी विफलताएं कुछ इस प्रकार हैं:-

क्षेत्र को स्वच्छ बनाने की दिशा में सरकारी एजेंसिया एकजुट नहीं हो सकीं।

कालोनियों के विकास के लिए बहुत काम किए जाने थे, जो नहीं हो सके।

सार्वजनिक परिवहन में बसों के चक्कर बढ़वाने के लिए कुछ नहीं हो सका।

एक्सप्रेस ट्रेनों के ठहराव की लंबे समय से चली आ रही मांग पूरी नहीं हुई।

कई इलाकों की जल निकासी की समस्या थी, जिसका अभी तक समाधान नहीं हो सका है।

सांसद निधि के उपयोग में कंजूसी नहीं

मनोज तिवारी ने सांसद निधि का उपयोग करने में कंजूसी नहीं दिखाई। उन्होंने अपनी निधि की लगभग 99.72 फीसदी राशि विकास कार्यों में खर्च की। इसके अलावा सोनिया विहार क्षेत्र के विकास को लेकर संसद में अपनी बात रखी। यमुना नदी को स्वच्छ बनाने और खेलों को बढ़ावा देने का मुद्दा भी संसद में उठाया।

निर्माण कार्यों में भी उनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा रहा। उन्होंने 14,500 करोड़ की कुल लागत से लोकसभा क्षेत्र के पहले केंद्रीय विद्यालय, पहले रेलवे स्टेशन, पहले एवं दिल्ली के सबसे लंबे एलिवेटेड रोड सहित कई अन्य विकास कार्य करवाए। इसके साथ ही लोकसभा का पहला पासपोर्ट केंद्र भी शुरू कराया।

क्या कहती है जनता

मनोज तिवारी के कार्यकाल को लेकर रामनगर की मीना कहती हैं, मध्य वर्गीय परिवार समस्याओं से जूझता है। महंगाई की मार झेल रहा है। हमारे सांसद को हमारी परेशानियों के समाधान के विषय में संसद में मुद्दे उठाने चाहिए और महंगाई पर अंकुश लगना चाहिए।

वहीं शाहदरा निवासी अनु भाटिया कहती हैं, ₹सांसद मनोज तिवारी अपने संसदीय क्षेत्र का विकास कर वहां की उन्नति का ध्यान रखा है। विकास के लिए उन्होंने कई विशेष काम भी कराए हैं, समस्याओं का निस्तारण भी कराया है।₹

लोनी रोड निवासी सावित्री का कहना है, ₹मैंने अपने क्षेत्र में कभी सांसद को आते नहीं देखा है। लोकसभा चुनाव जीतने के बाद जो भी नया सांसद बने उनको लोगों से मिलते-जुलते रहना चाहिए। इसके अलावा आम जनता से जुड़े मुद्दों को भी संसद में उठाना चाहिए।

क्या कहते हैं विरोधी

मनोज तिवारी को लेकर पूर्व कांग्रेस विधायक भीष्म शर्मा कहते हैं, ₹कांग्रेस के समय की परियोजनाओं पर क्रेडिट ले रहे हैं। सभापुर गांव को गोद लेकर आदर्श बनाने का दावा किया था, जिसकी हालत पांच साल बाद भी सुधर नहीं सकी है। इस गांव बिना वर्षा पानी सड़कों पर भरा रहता है। यही हाल पिछले कार्यकाल में गोद लिए गांव कादीपुर का है। चुनाव के दौर में क्षेत्र में दिखाई दे रहे हैं, सामान्य दिनों में दूर ही रहते हैं।

वहीं गोकलपुर से आम आदमी पार्टी के विधायक चौधरी सुरेंद्र कुमार का कहना है, मनोज तिवारी ने सांसद की जिम्मेदारी नहीं निभाई। क्षेत्र के लिए कोई उल्लेखनीय काम नहीं किया। वह अपने लोकसभा क्षेत्र से बाहर रहते हैं, किसी तरह से लोग प्रतिनिधियों के माध्यम से कालोनियों की समस्या को उन तक पहुंचाते हैं, वह विधायकों का काम बताकर उन्हें टाल देते हैं। केवल पार्टी की राजनीति करते रहे। आम जनता की समस्याओं से कोई लेना-देना नहीं है।

विकास के लिए किया काम

क्षेत्र के विकास के लिए लगातार काम किया। जाम की समस्या खत्म करने के लिए पुश्ता रोड पर दिल्ली-सहारनपुर हाईवे 709B का निर्माण कराया है, जोकि 90 प्रतिशत बन चुका है। 2018 में पहली मेट्रो लाने के बाद अब मौजपुर व बुराड़ी होते ट्रिपल डेकर मेट्रो कारिडोर बन रहा है। खजूरी वाला पार्क (5 एकड़) व राठी मिल पार्क (5 एकड़) के निर्माण सहित 42 पार्कों में जिम व झूले लगे हैं। यमुना किनारे रिवर फ्रंट में 10 झील बन रही हैं। -मनोज तिवारी, सांसद, उत्तर पूर्वी दिल्ली

मोदी के रोड शो को लेकर कई मार्ग बंद, कई रास्तों पर वाहन चालकों की पुलिसकर्मियों से हुई नोकझोंक

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी शनिवार शाम को गाजियाबाद में रोड शो करेंगे। इसको लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। उनके प्रस्तावित रोड शो के लिए पुलिस ने आज ही अंबेडकर रोड पर आवाजाही के अधिकांश कट बंद कर दिए हैं। इससे शहर के कई मार्गों पर वाहन चालकों को जाम से जूझकर निकलना पड़ रहा है। पूरे रोड पर अस्थाई बेरिडिंग की गई है।

गाजियाबाद। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के शनिवार शाम को प्रस्तावित रोड शो के लिए पुलिस ने आज ही अंबेडकर रोड पर आवाजाही के अधिकांश कट बंद कर दिए हैं। इससे शहर के कई मार्गों पर वाहन चालकों को जाम से जूझकर निकलना पड़ रहा है। पूरे रोड पर अस्थाई बेरिडिंग की गई है।

वहं, डिवाइडर पर पेंट का काम अभी तेजी से पूरा किया जा रहा है। कई कट पर वाहन चालक पुलिसकर्मियों से निकलने को लेकर नोकझोंक भी हुई। अंबेडकर रोड के व्यापारियों को पुलिस ने तीन दिन यानी आज से रविवार तक प्रतिष्ठानों के बाहर पार्किंग से मना किया है।

इन रास्तों को किया गया बंद

वसंत रोड से मालीवाड़ा चौक जाने वाले रास्ते

मालीवाड़ा चौक के कई रास्ते बंद

मालीवाड़ा चौक से पुराने बस अड्डे की तरफ

मालीवाड़ा चौक से चौधरी मोड़ की तरफ

अंबेडकर रोड को किया गया बंद

कालका गढ़ी चौक बंद

हेल्पलाइन नंबर की ले सकते हैं मदद

एडीसीपी यातायात वीरेंद्र कुमार ने लोगों से अपील की है कि वे छह अप्रैल को रूट डायवर्जन प्लान देखकर ही घर से निकलें, जिससे कि उनको आवागमन में परेशानी का सामना न करना पड़े। रूट डायवर्जन के दौरान कोई असुविधा होने पर यातायात हेल्पलाइन नंबर 0120 2986100, 9643322904 पर संपर्क कर सकते हैं।

गाजियाबाद में राहुल-अखिलेश को उतारेगा I.N.D.I.A, शीर्ष नेतृत्व से मिल चुकी सहमति

दिल्ली से सटी गाजियाबाद सीट पर चुनाव दिलचस्प होता जा रहा है। 6 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाजपा प्रत्याशी अतुल गर्ग के समर्थन में गाजियाबाद में रोड शो करने आ रहे हैं। इससे पहले राजनाथ सिंह ने गाजियाबाद से विपक्ष को जमकर घेरा था। अब आईएनडीआईए ने भी पीएम मोदी के जवाब में अखिलेश यादव और राहुल गांधी को उतारने की तैयार में है।

परिवहन विशेष न्यूज

गाजियाबाद। गाजियाबाद लोकसभा सीट पर चुनावी रण काफी दिलचस्प होता जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी व रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के जवाब में आईएनडीआईए (इंडी) ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को उतारने की पूरी तैयारी कर ली है।

जल्द ही इन नेताओं का क्षेत्र में रोड शो और चुनावी जनसभा होने की संभावना है। वहीं, बसपा ने भी कमर कस ली है। रविवार को पार्टी के स्टार प्रचारक नेशनल कोआर्डिनेटर आकाश आनंद की यहां चुनावी रैली होगी। भाजपा ने चुनाव की घोषणा होने के पहले ही विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से यहां वोट बैंक के बीज बोने का काम शुरू कर दिया था।

भाजपा ने झोंकी पूरी ताकत

अब उस फसल को काटने की पूरी तरह से जुगत लगा रही है। इसी के तहत यहां पार्टी के शीर्ष नेताओं का एक के बाद एक चुनावी कार्यक्रम हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन कर चुके हैं। यह सम्मेलन प्रबुद्ध वर्ग के जरिये उनसे जुड़े मतदाताओं तक पहुंचने के लिए था। इसके बाद रक्षामंत्री राजनाथ सिंह का चुनावी जनसभा हुई।

राजनीतिक के जानकारों की मानें तो सदर विधायक अतुल गर्ग का टिकट होने पर क्षत्रियों को लेकर चल रहीं चर्चाओं पर इस जनसभा से विराम लगाने की पूरी कोशिश की गई। इसी दौरान उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कार्यक्रम करके पिछड़ों को साधने की कोशिश की। अब शनिवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी खुद ही यहां पर रोड शो करने पहुंच रहे हैं।

राजनीतिक के जानकारों की मानें तो सदर विधायक अतुल गर्ग का टिकट होने पर क्षत्रियों को लेकर चल रहीं चर्चाओं पर इस जनसभा से विराम लगाने की पूरी कोशिश की गई। इसी दौरान उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कार्यक्रम करके पिछड़ों को साधने की कोशिश की। अब शनिवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी खुद ही यहां पर रोड शो करने पहुंच रहे हैं।

राहुल का रोड शो कराएगी INDI गठबंधन

इंडी गठबंधन ने कांग्रेस प्रत्याशी डॉली शर्मा पर एक बार फिर से यहां दांव लगाया है। डॉली शर्मा मौजूदा समय में पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के नाते शीर्ष नेतृत्व की करीबी मानी जाती हैं। लोकसभा चुनाव-2019 में उनके पक्ष में कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने घंटाघर से मालीवाड़ा तक रोड शो किया था। शनिवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का रोड शो भी इस क्षेत्र के कुछ हिस्सों से गुजरेगा।

कांग्रेसी इस बार भी इसी क्षेत्र के आसपास राहुल गांधी का रोड शो कराने की तैयारी में हैं। सूत्रों की मानें तो शीर्ष नेतृत्व की ओर से राहुल गांधी के रोड शो की सहमति मिल चुकी है। इसकी अनुमति आदि की कागजी प्रक्रिया पूरी होते ही उनका रोड शो होगा। वहीं, दूसरी ओर कांग्रेसी अखिलेश यादव की चुनावी जनसभा कराने की रणनीति तैयार की है। इसके लिए भी कार्यक्रम तैयार किया जा रहा है। जगह व समय तय होते ही उनकी जनसभा कराए जाएगी। इन दोनों नेताओं को मैदान में उतार कर कांग्रेस अपनी सीट पक्की करने की कोशिश करेगी।

कल आएंगे आकाश आनंद

लोकसभा चुनाव-2019 बसपा ने सपा से गठबंधन करने लड़ा था। इस बार दोनों पार्टियों की राहें जुदा हैं। सपा इंडी में शामिल हो गई है, जबकि बसपा अकेले चुनाव लड़ रही है। बसपा ने पहले यहां पंजाबी अंशय कालरा को टिकट दिया था। उनका टिकट काटकर अब क्षत्रिय बिरादारी के नंदकिशोर पुंढीर पर दांव लगाया है। बसपाई उन्हें पूरे दमखम से चुनाव लड़ाने का दावा कर रहे हैं। रविवार को आकाश आनंद उनके पक्ष में चुनावी रैली करके माहौल बनाने की कोशिश करेंगे। पार्टी सूत्रों की मानें तो चुनाव से पहले पार्टी सुप्रीमो मायावती को भी बुलाने की कोशिश की जाएगी।

गाजियाबाद में नामांकन पत्रों की जांच में 21 प्रत्याशी फेल, सिर्फ 14 हुए पास

शुक्रवार को गाजियाबाद में नामांकन पत्रों की जांच के दौरान कुल 35 प्रत्याशियों में भाजपा कांग्रेस और बसपा व अन्य पार्टियों के अलावा पांच निर्दलीय समेत 14 प्रत्याशियों के नामांकन वैध मिले। वहीं 21 नामांकन पत्रों को निरस्त कर दिया है। आठ अप्रैल को नाम वापस लेने की अंतिम तिथि है। इसके बाद गाजियाबाद सीट पर 26 अप्रैल को लोकसभा चुनाव के लिए मतदान होंगे।

परिवहन विशेष न्यूज

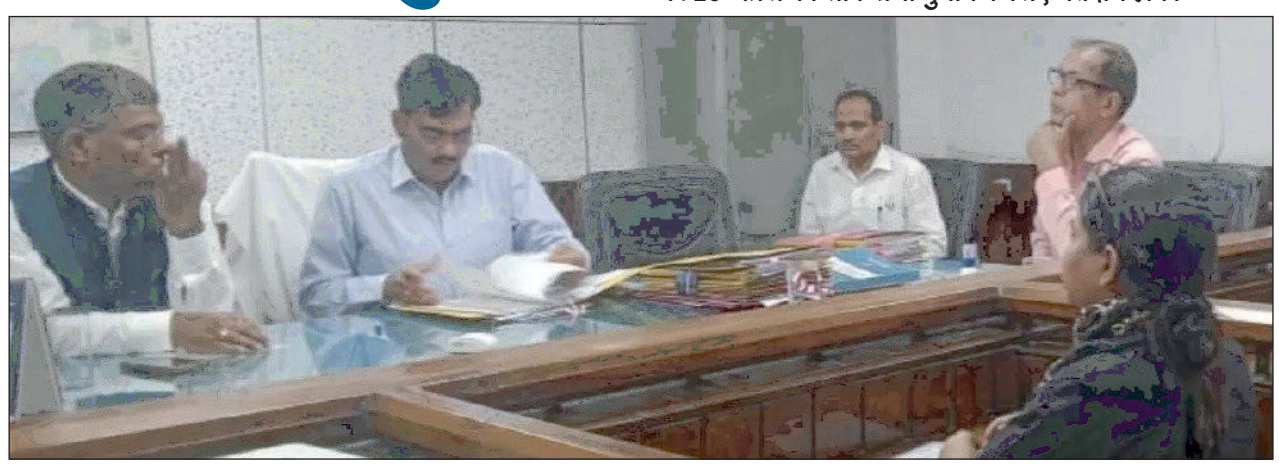

गाजियाबाद। गाजियाबाद संसदीय सीट पर दूसरे चरण में 26 अप्रैल को मतदान होगा। बृहस्पतिवार को नामांकन के अंतिम दिन बंपर नामांकन हुए और एक दिन में 22 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल किए। शुक्रवार को जांच के दौरान कुल 35 प्रत्याशियों में भाजपा, कांग्रेस और बसपा व अन्य पार्टियों के अलावा पांच निर्दलीय समेत 14 प्रत्याशियों के नामांकन वैध मिले।

35 प्रत्याशियों की भरा नामांकन

जिला निर्वाचन अधिकारी की ओर से 21 नामांकन पत्रों को निरस्त कर दिया गया। लोकसभा चुनाव की तैयारियों के बीच शुक्रवार को नामांकन पत्रों की जांच का कार्य पूरा किया गया। गाजियाबाद सीट पर भाजपा, कांग्रेस और बसपा समेत कुल 35 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया था।

शुक्रवार को जांच के दौरान राष्ट्रीय पार्टियों के तीनों प्रत्याशियों भाजपा से अतुल गर्ग, कांग्रेस की डॉली शर्मा और बसपा के नंदकिशोर पुण्डीर समेत 14 प्रत्याशियों के नामांकन जांच के दौरान सही पाए गए, जबकि नौ निर्दलीय समेत अन्य पार्टियों के 21 नामांकन पत्र निरस्त कर दिए गए। उक्त जानकारी देते हुए उप जिला निर्वाचन अधिकारी रणविजय सिंह ने बताया कि जिन प्रत्याशियों के नामांकन पत्र निरस्त किए गए हैं।

नामांकन के दौरान दाखिल किए गए शपथ पत्र, प्रारुप-2 और प्रमुख रूप से दर्ज की जाने वाली जानकारी भी अधूरी थीं। ऐसे नामांकन को निरस्त किया गया। उन्होंने बताया कि आठ अप्रैल को नाम वापस लेने की अंतिम तिथि है। इसके बाद चुनाव मैदान में डटे प्रत्याशियों के बीच 26 अप्रैल को मतदान होगा, जिसके नतीजे चार जून में सामने आएंगे।

चुनाव मैदान में यह उम्मीदवार

1. अतुल गर्ग, भारतीय जनता पार्टी
2. डॉली शर्मा- कांग्रेस
3. नंदकिशोर पुण्डीर, बहुजन समाज पार्टी
4. अवधेश कुमार, सुखी समाज पार्टी
5. आनन्द कुमार, राष्ट्र निर्माण पार्टी
6. अंशुल गुप्ता, राष्ट्रीय जन कर्मठ पार्टी
7. धीरेंद्र कुमार भदौरिया, सुभाषवादी भारतीय समाजवादी पार्टी
8. नमह, समाज विकास क्रान्ति पार्टी
9. पूजा, राइट टू रिकाल पार्टी
10. अभिषेक पुंडीर, निर्दलीय
11. औरंगजेब, निर्दलीय
12. कविता, निर्दलीय
13. नत्थू सिंह चौधरी, निर्दलीय
14. रवि कुमार पांचाल, निर्दलीय

इन प्रत्याशियों के नामांकन हुए निरस्त

मोनिका गौतम राष्ट्रीय सुरक्षा पार्टी, धर्मेंद्र कुमार भारतीय जनता दल, अनिल सिंह महिर सेना, मिथुन जायसवाल निर्दलीय,अमन कुमार निर्दलीय, रामप्रसाद पाण्डेय निर्दलीय, ललित मोहन त्यागी सनातन संस्कृति दल, कौशल सिंह निर्दलीय, अखिलेश कुमार निर्दलीय, वीरेंद्र कुमार पब्लिक पालीटिकल पार्टी, कुलभूषण त्यागी सम्राट मिहिर भोज समाज पार्टी, जुगनेश कुमार भारतीय शक्ति चेतना पार्टी, सोनी निर्दलीय, हरीशचन्द राष्ट्रीय समाज पक्ष, सुधीर कुमार निर्दलीय, मोहम्मद आलम नेशनल जन दल, शमशेर अली निर्दलीय, त्रिवेदी शर्मा नागरिक चेतना पार्टी, शमशेर राणा निर्दलीय, अमिता गुप्ता भारतीय महासंघ पार्टी, उदय सिंह भारतीय जवान किसान पार्टी से प्रत्याशी थे।

पीएम मोदी के रोड के दौरान इन चीजों के ले जाने पर बैन, गाजियाबाद पुलिस की पढ़ लें एडवाइजरी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को गाजियाबाद में रोड शो करेंगे। इसके लेकर प्रशासन ने तैयारी पहले से ही शुरू कर दी है। पुलिस ने इस संबंध में एडवाइजरी जारी की है। कई रास्तों की बैरिकेडिंग कर दी गई है। वहीं रोड शो में आनेवाले लोगों के लिए भी गाइडलाइंस जारी की गई है। इसमें कई ऐसी वस्तुएं हैं जिसे लाने पर रोक लगाई गई है।

गाजियाबाद। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी शनिवार को शहर में रोड शो करेंगे। शनिवार शाम को अंबेडकर रोड पर मालीवाड़ा चौक से चौधरी मोड़ तक भाजपा प्रत्याशी अतुल गर्ग के समर्थन में शहर की जनता के बीच रहेंगे। पुलिस ने सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एडवाइजरी जारी की है।

पुलिस ने इन चीजों को लाने पर लगाई रोक

कैमरा, दूरबीन, रिमोट कंट्रोल कार चाबी, छाता, हैंडबैग, ब्रीफकेस, थर्मस, टिफिन बाक्स, पानी की बोतल, छड़ी, बैग, ब्लेड, रेजर या किसी भी तरह का हथियार ले जाने पर पाबंदी।

फ्रेम किए हुए पोस्टर, बैनर लेकर रोड शो में पहुंचने पर पाबंदी।

फूलमाला, पंखुड़ियां, गुलदस्ते और स्मृति चिन्ह लेकर न जाएं।

किसी भी व्यक्ति के पास एक मोबाइल से अधिक फोन की अनुमति नहीं।

सिगरेट, माचिस, लाइटर, आतिशबाजी पर पाबंदी।

सड़क के दाहिने ओर बनी दर्शक दीर्घा में ही नागरिकों के खड़े होने की अनुमति होगी।

रोड शो के दौरान किसी भी व्यक्ति को वीवीआईपी के समानान्तर चलने या दौड़ने की अनुमति नहीं होगी।

ड्रोन, पैराग्लाइडर, हॉट बैलून सहित अन्य उड़ाने वाली वस्तुओं पर पाबंदी लगा दी गई है। उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।

हेल्पलाइन नंबर की ले सकते हैं मदद

एडीसीपी यातायात वीरेंद्र कुमार ने लोगों से अपील की है कि वे छह अप्रैल को रूट डायवर्जन प्लान देखकर ही घर से निकलें, जिससे कि उनको आवागमन में परेशानी का सामना न करना पड़े। रूट डायवर्जन के दौरान कोई असुविधा होने पर यातायात हेल्पलाइन नंबर 0120 2986100, 9643322904 पर संपर्क कर सकते हैं।

चुनाव के चलते शादी में आई रुकावट, वाहनों की बुकिंग में आ रही दिक्कत

पश्चिमी यूपी के कई लोकसभा सीटों पर दूसरे चरण में 26 अप्रैल को चुनाव है। चुनाव का असर शहनाई पर पड़ता दिख रहा है। वैवाहिक कार्यक्रमों पर चुनावी बिगुल भारी पड़ता दिख रहा है। सहालग के चलते शादी वाले घरों में चिंता बढ़ गई है। लोग वैवाहिक कार्यक्रम पीछे हटाने जैसे विकल्पों पर विचार कर रहे हैं तो कुछ ने कार्यक्रमों को चुनाव बाद टाल दिया है।

नोएडा। गौतमबुद्ध नगर, गाजियाबाद, बुलंदशहर लोकसभा सीटों पर दूसरे चरण में 26 अप्रैल को चुनाव है। चुनाव का असर शहनाई पर पड़ता दिख रहा है।

वैवाहिक कार्यक्रमों पर चुनावी बिगुल भारी पड़ता दिख रहा है। सहालग के चलते शादी वाले घरों में चिंता बढ़ गई है।

लोग वैवाहिक कार्यक्रम पीछे हटाने जैसे विकल्पों पर विचार कर रहे हैं तो कुछ ने कार्यक्रमों को चुनाव बाद टाल दिया है। इसके पीछे वाहनों की दिक्कत होने से लेकर अन्य परेशानी होने जैसे तर्क दे रहे हैं।

13 अप्रैल को खत्म होगा खरमास

पंडित संतोष शुक्ला ने बताया कि होली के आसपास शुरू हुआ खरमास 13 अप्रैल को खत्म हो गया। अप्रैल माह में 18 से 26 और 28 अप्रैल को शुभ मुहूर्त है। इसके मई माह में भी सहालग के लिए शुभ दिन हैं।

इसको लेकर जनपद और आसपास के जिलों में भी वैवाहिक कार्यक्रम होने हैं, लेकिन इस बीच लोक सभा चुनाव भी है।

चुनाव के चलते वाहनों की बुकिंग में हो रही दिक्कत

अपने बड़े बेटे की शादी पक्की कर चुके जहांगीरपुर के रहने वाले गुलवीर शर्मा ने बताया कि 14 अप्रैल को बेटे की रिंग सेरेमनी है, जबकि 18 अप्रैल को शादी व 20 अप्रैल को रिशेप्सन है। दो कार्यक्रम जनपद से बाहर हैं।

वैवाहिक कार्यक्रमों को लेकर घर में तैयारियां की जा रही हैं, लेकिन चुनाव होने के चलते कुछ परेशानियां आ रही हैं। सबसे ज्यादा संकट वाहनों की बुकिंग को लेकर है।

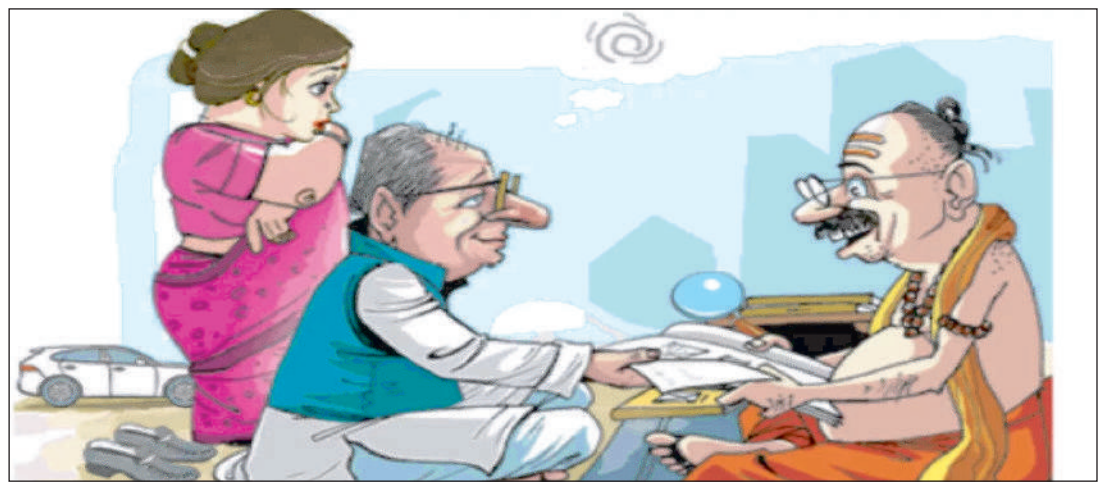

कार मालिक वाहन की बुकिंग के लिए अनाप शनाप रुपये मांग रहे हैं।

वर पक्ष ने कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की मांग की

नोएडा के निठारी के रहने वाले सोनू ने बताया कि 24 अप्रैल को छोटी बहन की सगाई है। वर पक्ष वाले बरेली के रहने वाले हैं। चुनाव की तिथि को लेकर वर पक्ष ने कार्यक्रम को आगे बढ़ाने को लेकर बात रखी थी। इस पर विचार किया जा रहा है।

दोनों पक्षों के बीच लगभग सहमति बन गई है। इस तरह से विवाह घर, बैंक्वेट संचालक व डेकोरेशन की बुकिंग वालों के लिए चुनाव की तिथि परेशानी बन रही हैं। चुनाव और सहालग के बीच सभी की मांग पूरी करना प्रभावित हो रहा है।

सामुदायिक भवन में पोलिंग पार्टियां, कहां बजे शहनाई

ग्रेटर नोएडा और नोएडा के सेक्टर, गांव व कॉलोनियों में एक से दो सामुदायिक भवन हैं। नोएडा में ही 180 से ज्यादा सामुदायिक भवन हैं। अधिकांश भवनों को चुनाव के लिए हायर कर लिया गया है। इनमें पोलिंग पार्टियों के रुकने का प्रबंध किया जाए रहा है।

ऐसे में सहालग में वैवाहिक कार्यक्रम होने प्रभावित हैं। लोगों के समक्ष दुविधा हो गई है कि वह कार्यक्रम को कहां पर आयोजित करें। उनके पास निजी होटल व बैंक्वेट जाना ही विकल्प रह गया है।

वाहन किराया पहले किराया अब

छोटी कार	12	16
इनोवा	17	22
टैवलर	23	26-28

नोटः सभी रेट प्रति किलोमीटर के हिसाब से हैं।

क्या बोले संचालक

नोएडा में ट्रैवल एजेंसी मालिक भूपेश ने बताया कि चुनाव के दौरान प्रक्रिया में वाहनों की मांग रहती है। पुलिस प्रशासन की ओर से भी वाहन हायर किये जाते हैं। दूसरे चरण के बीच चुनाव दौरान लगातार साया भी है। इस बीच वाहनों की मांग ज्यादा है।

नोएडा में रामा ग्रुप आफ बैंक्वेट के सीएमडी अमरजीत सिंह ने बताया कि पिछले साल के मुकाबले सहालग अच्छा है। चुनाव की घोषणा से पहले बुकिंग फुल हो गई थीं। कुछ लोगों ने बुकिंग कैंसिल कराई हैं और तिथियों को आगे बढ़ाया है लेकिन 28 अप्रैल तक लेकर कोई भी बुकिंग खाली नहीं है।

एल्विश यादव समेत आठ आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर, फिलहाल जमानत पर हैं जेल से बाहर

यूट्यूबर एल्विश यादव समेत आठ लोगों के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया है। नवंबर 2023 में नोएडा की कोतवाली सेक्टर-49 में एल्विश समेत छह लोगों के खिलाफ सर्प विष तस्करी के आरोप में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। हाल ही में पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया था और पांच दिन बाद ही उन्हें जमानत भी मिल गई थी।

नोएडा। रेव पार्टी आयोजित करने और उसमें सांपों का जहर सप्लाई करने के मामले में फंसे यूट्यूबर एल्विश यादव के खिलाफ नोएडा पुलिस ने संबंधित न्यायालय में 1200 पन्नों का आरोप पत्र शुक्रवार को दाखिल कर दिया। इसमें 24 गवाहों के बयान दर्ज किए गए हैं। आरोप पत्र में नोएडा पुलिस की ओर से बताया गया है कि एल्विश का जहरीले खेल में जेल भेजे गए सपेरों से संपर्क था।

एल्विश के खिलाफ लगी एनडीपीएस की धाराओं का आधार भी पुलिस ने इसमें बताया है। एल्विश और उसके सहयोगियों पर लगे आरोपों की पुष्टि नोएडा पुलिस द्वारा आरोप पत्र में की गई है। इसमें मुंबई स्थित डिपार्टमेंट आफ फारेंसिक मेडिसीन टाक्सिकोलाजी के विशेषज्ञ की सलाह भी शामिल की गई है।

3 नवंबर 2023 को कोतवाली सेक्टर-49 में पीपुल्स फार एनिमल संस्था के पदाधिकारी गौरव गुप्ता ने एल्विश यादव और उसके साथियों पर सांपों के जहर का इस्तेमाल करने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया था।

ऑपरेशन चक्रव्यूह चलाकर एल्विश को दबोचा गया

संस्था के सदस्य ने एक स्टिंग किया था। इसमें कोबरा समेत नौ सांप और 20 एमएल सांपों का जहर पांच सपेरों के पास मिला। सभी को जेल भेज दिया गया। संस्था के पदाधिकारी का एक आडियो इसके बाद प्रसारित हुआ था जिसमें मुख्य आरोपित राहुल संस्था के पदाधिकारी से बात कर रहा है। इसमें राहुल यह कह रहा है कि वह एल्विश की ओर से आयोजित होने वाली पार्टियों में शामिल हो चुका है। राहुल पार्टियों में अपने अन्य सपेरे दोस्तों के साथ गया था। हालांकि बाद में सभी को जमानत मिल गई। इसके बाद एल्विश को दबोचने के लिए पुलिस ने ऑपरेशन चक्रव्यूह तैयार किया।

जयपुर से आई फॉरेंसिक रिपोर्ट का अध्ययन

देश भर में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत दर्ज केस का नोएडा पुलिस की एक टीम ने अवलोकन किया। एक अन्य टीम ने जयपुर से आई फॉरेंसिक रिपोर्ट का अध्ययन किया। रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि हुई थी सांपों का जो जहर सपेरों के पास से मिला था वह करैत प्रजाति के कोबरा का है।

कंपनी ने जितना बताया, उतनी रेंज नहीं दे पा रही इलेक्ट्रिक कार? इन तरीकों से तुरंत होगा फायदा

इलेक्ट्रिक कार का टॉर्क काफी हाई होता है और ऐसे में अगर आप शुरुआत के समय हल्का थ्रोटल देते हैं तो बैटरी पर कम लोड पड़ेगे और पावर सेव करने में मद मिलेगी। अगर कोई कंपनी एक निश्चित रेंज के आंकड़े का दावा कर रही है तो इसका मतलब यह नहीं है कि आपको रियल वर्ल्ड में बिल्कुल वही आंकड़ा मिलेगा।

नईदिल्ली। क्या आपकी इलेक्ट्रिक कार क्लेम्ड रेंज नहीं दे रही है? जवाब 'हां' है, तो हमारा ये लेख आपकी मदद कर सकता है। जिस तरह इंजन किसी पारंपरिक कार के लिए सबसे जरूरी चीज है, ठीक वैसे ही बैटरी Electric Car की सर्वेसर्वा है। आइए कुछ सरल तरकीबों के बारे में जान लेते हैं, जिनसे आप EV की रेंज बेहतर कर सकते हैं।

स्मूद ड्राइविंग करें

इलेक्ट्रिक कार का टॉर्क काफी हाई होता है और ऐसे में अगर आप शुरुआत के समय हल्का थ्रोटल देते हैं, तो बैटरी पर कम लोड पड़ेगे और पावर सेव करने में मद मिलेगी। जिस तरह स्मूद ड्राइविंग करके पेट्रोल या डीजल कारों का माइलेज बढ़ाया जा सकता है, ठीक वहीं फॉर्मूला इधर भी लागू होता है।

रिजेनरेटिव ब्रेकिंग यूज करें

इलेक्ट्रिक कार में रिजेनरेटिव ब्रेकिंग का उपयोग करके रेंज बढ़ाई जा सकती है। जब आप थ्रोटल से पैर हटा देते हैं, तो कार में लगा एक अल्टरनेटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। इसकी मदद से बैटरी को थोड़ा पावर मिल जाती है।

क्रूज कंट्रोल से बचें

एक ओर क्रूज कंट्रोल से पेट्रोल और डीजल की बचत होती है, वहीं इलेक्ट्रिक कार में इसका उलट सिस्टम है। कार से बेहतरीन रेंज पाने के लिए आपको नियंत्रित ड्राइविंग करनी होगी।

क्यों नहीं मिलती क्लेम्ड रेंज?

अगर कोई कंपनी एक निश्चित रेंज के आंकड़े का दावा कर रही है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि आपको रियल वर्ल्ड में बिल्कुल वही आंकड़ा मिलेगा। ईवी की रेंज एक पारंपरिक कार के माइलेज की तरह, परीक्षणों के दौरान नियंत्रित परिस्थितियों आंकी जाती है। इस वजह से ग्राहकों को वह रेंज नहीं मिल पाती, जो कंपनियां क्लेम करती हैं।

टोयोटा अर्बन क्रूजर टैसर केवल 7.73 लाख रुपये में हुई लॉन्च, इतनी खास है कंपनी की सबसे अफोर्डेबल एसयूवी

टोयोटा अर्बन क्रूजर टैसर कीमत 7.73 लाख रुपये (एक्स-शोरूम दिल्ली) से शुरू होती है और ये Maruti Suzuki Fronx पर आधारित एक सबकॉम्पैक्ट एसयूवी है। एसयूवी को अपडेटेड एलईडी टेललाइट्स भी दिए गए हैं जो बूट पर लाइट बार के माध्यम से कनेक्ट होते हैं। इसके अलावा मॉडल में नए स्टाइल वाले अलॉय व्हील भी हैं। Taisor में रेक्ड रियर विंडस्क्रीन बरकरार है जो मॉडल को स्टाइलिश लुक देती है।

नई दिल्ली। टोयोटा किर्लोस्कर मोटर (TKM) ने Urban Cruiser Taisor के रूप में देश में अपनी सबसे अफोर्डेबल एसयूवी पेश की है। नई टोयोटा अर्बन क्रूजर टैसर की कीमत 7.73 लाख रुपये (एक्स-शोरूम, दिल्ली) से शुरू होती है और ये Maruti Suzuki Fronx पर आधारित एक सबकॉम्पैक्ट एसयूवी है। आइए, इस बैज-इंजीनियर्ड पेशकश के बारे में जान लेते हैं।

डिजाइन और डायमेंशन

नई अर्बन क्रूजर टैसर का रेशियो फ्रोंक्स के समान ही है। हालांकि इसे नया लुक देने के लिए फ्रंट को अपडेट किया गया है। कूप-स्टाइल सबकॉम्पैक्ट एसयूवी को हनीकॉम्ब मेश ग्रिल और सेंटर में टोयोटा लोगो के साथ नए ट्विन एलईडी डीआरएल दिए गए हैं। एसयूवी को अपडेटेड एलईडी टेललाइट्स भी दिए गए हैं, जो बूट पर लाइट बार के माध्यम से कनेक्ट होते हैं। इसके अलावा मॉडल में नए स्टाइल वाले अलॉय व्हील भी हैं। Taisor में रेक्ड रियर विंडस्क्रीन बरकरार है, जो मॉडल को स्टाइलिश लुक देती है।

इंटीरियर

इसका केबिन काफी हद तक मारुति सुजुकी फ्रोंक्स के समान है। इसमें 9-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और सेंटर में एमआईडी यूनिट के साथ ट्विन-पॉड इंस्ट्रूमेंट कंसोल है। केबिन में नया डुअल-टोन ट्रीटमेंट दिया गया है।

फीचर्स

टोयोटा टैसर में ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, कनेक्टेड कार तकनीक, वायरलेस एपल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो कनेक्टिविटी, 360-डिग्री कैमरा, हेड-अप डिस्प्ले, क्रूज कंट्रोल और डीआरएल के साथ ऑटोमैटिक एलईडी हेडलैंप जैसे फीचर्स मिलते हैं। इसके अलावा ये सबकॉम्पैक्ट एसयूवी 6-स्पीकर साउंड सिस्टम, पुश-बटन स्टार्ट/स्टॉप और रियर एसी वेंट के साथ आती है।

इंजन और परफॉरमेंस

नई टोयोटा टैसर को 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड और 1.0-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन विकल्पों के साथ पेश किया गया है। 1.2 मोटर 89 बीएचपी और 113 एनएम पीक टॉर्क पैदा करता है, जबकि टर्बोचार्ज्ड यूनिट 99 बीएचपी और 148 एनएम पीक टॉर्क पैदा करता है।

ट्रांसमिशन विकल्पों में दोनों पावर मिलों के साथ 5-स्पीड मैनुअल शामिल है, जबकि नैचुरली एस्पिरेटेड मोटर को 5-स्पीड एएमटी और टर्बो पेट्रोल को 6-स्पीड टॉर्क कनवर्टर मिलता है। इसमें सीएनजी पावरट्रेन भी उपलब्ध है।

KTM 250 Duke को मिला नया कलर, पहले से लग रही है जबरदस्त; कीमतों में नहीं हुआ कोई बदलाव

KTM 250 Duke को नए अटलांटिक ब्लू रंग कलर ऑप्शन के साथ पेश किया गया है। इस नई पेंट स्कीम के साथ 250 ड्यूक अब सिरेमिक व्हाइट इलेक्ट्रिक ऑरेंज और नए अटलांटिक ब्लू में उपलब्ध है। इसकी कीमत में कोई बदलाव नहीं किया गया है। आप इसे 2.39 लाख रुपये एक्स-शोरूम कीमत पर खरीद सकते हैं। आइए इसके बारे में जान लेते हैं।

नई दिल्ली। KTM India ने 250 Duke को नए अटलांटिक ब्लू रंग कलर ऑप्शन के साथ पेश किया है। नए डुअल-टोन काले और नीले रंग को दोपहिया वाहन निर्माता के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रदर्शित किया गया है। इससे पहले, अटलांटिक ब्लू केवल 390 Duke पर उपलब्ध था।

KTM 250 Duke का नया कलर

इस नई पेंट स्कीम के साथ 250 ड्यूक अब सिरेमिक व्हाइट, इलेक्ट्रिक ऑरेंज और नए अटलांटिक ब्लू में उपलब्ध है। इसकी कीमत में कोई बदलाव नहीं किया गया है। आप इसे 2.39 लाख रुपये, एक्स-शोरूम कीमत पर खरीद सकते हैं।

नए ब्लैक और ब्लू कलर कॉम्बिनेशन में हेडलाइट काउल, फ्रंट मडगार्ड, फ्यूल टैंक और इसके एक्सटेंशन और सैडल के नीचे साइड पैनल शामिल हैं। ड्यूक नेमप्लेट और अलॉय व्हील ऑस्ट्रियाई ब्रांड के सिग्नेचर ऑरेंज शेड को जारी रखते हैं। इसकी स्प्लिट सीट्स पूरी तरह से ब्लैक है।

इंजन और परफॉरमेंस

KTM 250 Duke में कोई मैकेनिकल बदलाव नहीं किया गया है। इसे 249cc सिंगल-सिलेंडर लिक्विड-कूल्ड इंजन द्वारा संचालित किया जाता है, जो 30.5 bhp और 25 Nm का टॉर्क पैदा करता है। इसे 6-स्पीड गियरबॉक्स से जोड़ा गया है।

स्पेसिफिकेशन और डायमेंशन

हार्डवेयर के संदर्भ में 250 ड्यूक 43 मिमी फ्रंट फोर्क्स और 10-स्टेप प्रीलोड एडजस्टमेंट के साथ एक रियर मोनोशॉक के साथ आता है। पावर को रोकने के लिए इसमें 320mm फ्रंट डिस्क और 240mm रियर डिस्क है। इसकी टैंक क्षमता 15 लीटर, ग्राउंड क्लीयरेंस 176 मिमी और सैडल हाइट 800/820 मिमी है।

Kia ने बनाया मेगाप्लान, गैसौलीन और हाइब्रिड व्हीकल्स के लिए 28 बिलियन डॉलर का होगा निवेश

कंपनी ने एक बयान में कहा कि जीरो-एमीशन कारों की कम मांग के बावजूद यह बड़े पैमाने पर बाजार मॉडल के साथ अपने ईवी लाइनअप को मजबूत करना जारी रखेगी। कंपनी इस साल की शुरुआत में घरेलू बाजार में धीरे-धीरे तीन नई ऑल-इलेक्ट्रिक एसयूवी - ईवी3 ईवी4 और ईवी5 लॉन्च करने की योजना बना रही है। कंपनी 28 बिलियन डॉलर का निवेश करने जा रही है।

नईदिल्ली। किआ ने शुक्रवार को कहा कि वह इलेक्ट्रिक वाहनों की धीमी बिक्री के बीच अपने गैसोलीन हाइब्रिड वाहन लाइनअप को मजबूत करते हुए 2028 तक भविष्य के गतिशीलता समाधानों में 38 ट्रिलियन वोन (28 बिलियन डॉलर) का निवेश करेगी। अगले पांच वर्षों में नियोजित निवेश को पिछले साल घोषित 33 ट्रिलियन वोन से संशोधित किया गया है।

EV की मांग घटेगी?

योनहाप समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, कंपनी ने इस साल के सीईओ निवेशक दिवस पर कहा, किआ को उम्मीद है कि आर्थिक मंदी, कम सरकारी सब्सिडी, चार्जिंग बुनियादी ढांचे की कमी के कारण इस साल ईवी बिक्री वृद्धि धीमी हो जाएगी।

हाइब्रिड कारों में होगी बढ़ोतरी

किआ के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी सोंग हो-सुंग ने कहा, ₹प्रतिद्वंद्वियों के साथ कड़ी प्रतिस्पर्धा और बढ़ती भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं का सामना करते हुए, कंपनी तेजी से बदलते बाजार रुझानों का लचीले ढंग से जवाब देगी और जोखिमों को अवसरों में बदलेगी।₹

के5 सेडान और सोरेंटो एसयूवी के निर्माता ने कहा कि वह आने वाले वर्षों में अपने लाइनअप में अधिक गैसोलीन हाइब्रिड मॉडल जोड़ेगी। किआ ने अनुमान लगाया कि उसकी कुल वाहन बिक्री में गैसोलीन हाइब्रिड मॉडल का अनुपात बढ़कर 19 प्रतिशत या 800,000 यूनिट हो जाएगा।

इलेक्ट्रिक कारों पर भी रहेगा फोकस

कंपनी ने एक बयान में कहा कि जीरो-एमीशन कारों की कम मांग के बावजूद यह बड़े पैमाने पर बाजार मॉडल के साथ अपने ईवी लाइनअप को मजबूत करना जारी रखेगी। कंपनी इस साल की शुरुआत में घरेलू बाजार में धीरे-धीरे तीन नई ऑल-इलेक्ट्रिक एसयूवी - ईवी3, ईवी4 और ईवी5 लॉन्च करने की योजना बना रही है।

पंजाब में अकाली-भाजपा गठबंधन टूटा

कुलदीप चंद अग्निहोत्री

पंजाब में अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी लम्बे अरसे से मिल कर चुनाव लडने के आदी हो गए थे। इतिहास में देखा जाए तो मिलने-टूटने का यह सिलसिला 1967 के विधानसभा चुनावों के बाद ही शुरू हो गया था।

दरअसल अकाली दल की दुविधा यह है कि वह सिख समुदाय को एक विशिष्ट राजनीतिक ईकाई के तौर पर देखता है। उसे लगता है कि जो सिख अकाली दल के साथ है, वह तो सिख है, लेकिन जो सिख कम्युनिस्ट पार्टी, कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी या समाजवादी पार्टी के साथ है, वह सिख नहीं है'

पंजाब में अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी लम्बे अरसे से मिल कर चुनाव लडने के आदी हो गए थे। इतिहास में देखा जाए तो मिलने-टूटने का यह सिलसिला 1967 के विधानसभा चुनावों के बाद ही शुरू हो गया था। बीच-बीच में मन-मुटाव भी हुआ लेकिन अब पिछले तीन दशकों से आपसी गठबन्धन ठीक-ठाक ही चल रहा था। किसान आन्दोलन से घबरा कर अकाली दल ने भाजपा से संबंध तोड़ लिया। अकाली दल को लगा कि पंजाब भाजपा के खिलाफ किसान आन्दोलन के नेताओं के साथ हो लिया है। ऐसी स्थिति में भाजपा के खिलाफ खड़ा होना हाराकिरी करने के समान होगा। लेकिन अकाली दल का आकलन कम से कम इस मुद्दे पर गलत था कि पंजाब किसान नेताओं के साथ है। 2022 के विधानसभा चुनावों में किसान आन्दोलन में से उपजी नई पार्टी संयुक्त किसान मोर्चा के सभी लोगों की जमानत जब्त हो गई। दरअसल किसान मोर्चा एक बहुत ही कुशल रणनीति और मैनेजमेंट के कौशल में से पैदा हुआ था। इस कौशल ने शून्य तो उत्पन्न करने की कोशिश की, लेकिन इस कौशल के नेताओं को जन नेता नहीं बना सका। केजरीवाल को कुछ देसी विदेशी शक्तियां 2014 में से ही राष्ट्रीय रंगमंच पर लाँच करने का प्रयास करती रही थीं। अलबत्ता वहां तो सफलता नहीं मिली, लेकिन पंजाब में जरूर सफलता मिल गई। वैसे भी किसान आन्दोलन में सक्रिय कम्युनिस्ट कैडर ने आम आदमी पार्टी की सहायता की थी।

भारतीय जनता पार्टी वोटों और सीटों के मामले में वहीं पहुंच गई जहां वह अकाली दल से गठबन्धन से पूर्व हुआ करती थी। वोट प्रतिशत लगभग छह सात के बीच और सीटें शून्य से आठ के बीच। वैसे इस चुनाव में भाजपा को दो सीटें और 6.6 फीसदी वोट मिले थे। सबसे ज्यादा नुकसान अकाली दल को हुआ। सीटें तीन। जहां तक वोट प्रतिशत का सवाल है अकाली दल को 18.38 प्रतिशत वोट मिले थे। लेकिन सबसे ज्यादा लाभ आम आदमी पार्टी को हुआ जिसने 117 सदस्यों की विधानसभा में से 92 सीटें झटक लीं। इस नए राजनीतिक माहौल में कांग्रेस और अकाली दल में भगदड़ मचना लाजिमी थी। लेकिन आश्चर्य की बात थी कि कांग्रेस और अकाली दल छोड़ कर लोग भाजपा में आने लगे और कुछ महीने पहले तक एक बार फिर अकाली-भाजपा गठबन्धन की चर्चा चल निकली। इसलिए जल्दी में फिर से एक लघु किसान आन्दोलन खड़ा हो गया। अकाली दल फिर घबराहट में आ गया। दरअसल पंजाब में किसान आन्दोलन अकाली दल को डराने-हडक़ाने का एक कारगार हथियार बन चुका है। अकाली दल इसको देख कर वैसी ही प्रतिक्रिया करता है जैसी किसान आन्दोलन के आयोजकों को आशा होती है। कहीं न कहीं इससे पंजाब में शासन कर रही पार्टी की हित साधना भी होती है। कहा जाता है और धरातल पर दिखाई भी देता था कि पिछले किसान आन्दोलन में पंजाब की उस समय की शासक पार्टी की प्रत्यक्ष ही भागीदारी थी और इस बार के किसान आन्दोलन में आम आदमी पार्टी की सक्रिय भागीदारी देखी जा सकती है। परिणाम वही हुआ। अकाली दल गठबन्धन की बातचीत से बाहर हो गया। यह ठीक है कि इसमें सीटों की संख्या भी एक मुद्दा रहा होगा लेकिन जिस कारक ने अकाली दल को गठबन्धन के राऊंड टेबल से हड़बड़ाहट में उठा दिया, वह किसान आन्दोलन ही था। इस गठबन्धन की बात सिरे न चढने से सबसे ज्यादा ख़ुशी शायद भाजपा के कार्यकर्ता को ही हो रही है। भाजपा के साधारण कार्यकर्ता को लगता है कि अकाली दल से गठबन्धन के कारण पंजाब में पार्टी का विकास रुकता है। यह ऊपर से देखने पर ठीक लगता है। लेकिन वस्तुस्थिति ऐसी नहीं है। दरअसल पंजाब में भूगोल के आधार पर पांच भाग हैं। मालवा, बाँगर, पुआध, दोआबा और माझा। भाजपा का आधार मोटे तौर पर 'पुआध' क्षेत्र के कुछ हिस्सों पर रहता है, जहां उसका मुकाबला अकाली दल से नहीं बल्कि कांग्रेस से होता है। पंजाब का दूसरा हिस्सा जहां भाजपा का कुछ आधार है वह 'बाँगर' क्षेत्र है जो राजस्थान से लगता है। वहां भी उसका मुकाबला कांग्रेस से ही होता है।

भाजपा का कुछ आधार जीटी रोड के शहरों में है और वहां भी उसकी प्रतिद्वन्द्वी पार्टी कांग्रेस होती है, अकाली दल नहीं। पंजाब में भाजपा की प्रगति न होने के अन्य बीसियों कारण हैं जिसमें जनसांख्यिकी प्रमुख है, लेकिन उसमें कम से कम अकाली दल नहीं है। पिछले कुछ अरसे से नरेन्द्र मोदी की रणनीति के चलते पंजाब की जनसांख्यिकी को ध्यान में रखते हुए भाजपा ने कार्य विस्तार के प्रयत्न शुरू किए हैं। इस कार्य विस्तार के दो ही तरीके हैं। पहला नीचे धरातल पर कैडर निर्माण किया जाए और उसमें से नेतृत्व उभरे। यह लम्बा तरीका है और चुनाव सिर पर हैं। दूसरा तरीका है कि पंजाब की जनसांख्यिकी को ध्यान में रखते हुए उसी के अनुरूप नेतृत्व खड़ा कर लिया जाए और उसकी सहायता से कैडर निर्माण किया जाए। फिलहाल पंजाब में भाजपा ने यह दूसरा तरीका ही इस्तेमाल किया है। अन्य दलों से अनेक नेता भाजपा में आ रहे हैं। रवनीत बिट्टू नया चेहरा है। लेकिन उससे बहुत पहले कांग्रेस-अकाली दल से आने-जाने का सिलसिला शुरू हो गया था। मनप्रीत सिंह बादल उनमें बड़ा चेहरा था। अकाली दल के वरिष्ठ नेता सिकन्दर सिंह मलूका की पुत्रवधू परमपाल कौर सिद्धू ने तो भारतीय प्रशासनिक सेवा से त्यागपत्र दे दिया है। उसकी चर्चा है कि वह भाजपा में शामिल हो रही है। ऐसे और भी उदाहरण हैं। भाजपा ने अभी जिन सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित किए हैं उनमें गुरदासपुर को छोड़ कर ज्यादा प्रत्याशी वही हैं जो दूसरे दलों को छोड़ कर भाजपा में आए हैं। अमृतसर के तरणजीत सिंह संधू को अपवाद कहा जा सकता है। लेकिन यह भी ध्यान रखना होगा कि इन इलाकों में भाजपा का अपना जनाधार उतना नहीं है कि अपने बलबूते चुनाव की लड़ाई लड़ सके। प्रत्याशी खड़े करने के दो उद्देश्य होते हैं, या तो प्रतीकात्मक लड़ाई या फिर जीतने के लिए रणनीति। भाजपा को लगता है कि जब चार सौ के पार का नारा दिया है तो लड़ाई प्रतीकात्मक नहीं हो सकती बल्कि जीतने की रणनीति ही बनानी होगी। पंजाब में शायद भाजपा इसी रणनीति के तहत काम कर रही है।

एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि पंजाब में भाजपा को पंजाबियों की प्रतिनिधि पार्टी बनना होगा, जनसंख्या में से किसी एक दो बिरादरियों की प्रतिनिधि पार्टी नहीं। भाजपा पंजाब में अब सभी पंजाबियों की पार्टी बनने की कोशिश कर रही है। अकाली दल ने शायद अब फिर से निर्णय कर लिया है कि उसे अन्ततः फिर से अपने पुराने खोल में ही सिमटना है। यही कारण है कि उसने हाल ही में पांथिक हितों और पंजाब के हितों में भेद करना शुरू कर दिया है। अब वह अपने आपको पांथिक हितों की पार्टी के तौर पर स्थापित करने के प्रयास में है। लेकिन अकाली दल यह स्पष्ट नहीं कर रहा कि पंजाब के हित और पांथिक हित आपस में विरोधी कैसे हैं या फिर अलग अलग कैसे हैं? दरअसल अकाली दल की दुविधा यह है कि वह सिख समुदाय को एक विशिष्ट राजनीतिक ईकाई के तौर पर देखता है। उसे लगता है कि जो सिख अकाली दल के साथ है, वह तो सिख है, लेकिन जो सिख कम्युनिस्ट पार्टी, कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी या समाजवादी पार्टी के साथ है, वह सिख नहीं है। जो सिख अकाली दल के अतिरिक्त किसी दूसरे राजनीतिक दल के साथ चला जाता है वह उसकी दृष्टि में पांथिक हितों का विरोधी हो जाता है।

पंजाब में अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी लम्बे अरसे से मिल कर चुनाव लडने के आदी हो गए थे। इतिहास में देखा जाए तो मिलने-टूटने का यह सिलसिला 1967 के विधानसभा चुनावों के बाद ही शुरू हो गया था।

संपादक की कलम से

बाबा 'एलोपैथी' विरोधी क्यों?

बाबा रामदेव कई मायनों में श्रद्धेय हैं। कमोबेश इस दौर के 'योग-पुरुष' हैं, जिन्होंने एक कड़ी साधना को इतना आसान बना दिया है कि औसत पार्क या सभा-स्थलों पर असंख्य लोग योगासन करते देखे जा सकते हैं। नतीजतन स्वास्थ्य में भी सुधार हो रहा है। ऐसे 'योग-साधक' को सर्वोच्च अदालत में माफीनामा देना पड़े और न्यायिक पीठ उसे स्वीकार करने के बजाय महज 'जुबानी जमा खर्च' करार दे, तो शीर्ष अदालत की इस कड़ी चेतावनी को समझना बेहद जरूरी है। बाबा की कंपनी 'पतंजलि आयुर्वेद' एक लंबे समय से भ्रामक प्रचार करती रही है कि उसके पास ग्लूकोमा, मधुमेह, रक्तचाप, अर्थराइटिस और अस्थमा सरीखी घातक बीमारियों के स्थायी इलाज हैं। दरअसल बाबा रामदेव ही पतंजलि के उत्पादों के सार्वजनिक चेहरा हैं। विज्ञापनों में वह दावे करते देखे जा सकते हैं कि उनकी औषधियां साक्ष्य आधारित, शोधपरक और लोगों पर परखी जा चुकी हैं। इन विज्ञापनों के व्यापक प्रभाव भी होते हैं, क्योंकि करोड़ों लोगों की बाबा में आस्था है। बाबा के दावों को सच मानते हुए असंख्य लोग पतंजलि की दवाएं खरीदते और इस्तेमाल करते हैं। नतीजतन आज बाबा की कंपनियों का टर्नओवर हजारों करोड़ रुपए है। पतंजलि दवाओं के प्रचार करने के साथ-साथ बाबा रामदेव आधुनिक चिकित्सा प्रणाली 'एलोपैथी' के खिलाफ विष-वमन भी करते रहे हैं। बाबा ऐसा क्यों करते हैं? पतंजलि के अलावा, झंडु, बैद्यनाथ, हमदर्द, डाबर आदि प्रख्यात कंपनियां भी आयुर्वेद औषधियों का व्यापक स्तर पर उत्पादन करती हैं। उन्होंने तो कभी भी 'एलोपैथी' के खिलाफ जहर नहीं उगला। सर्वोच्च अदालत ने इस भ्रामक और गलत प्रचार के लिए बाबा रामदेव को मना भी किया था, लेकिन बाबा और पतंजलि समूह के प्रबंध निदेशक आचार्य बालकृष्ण देश की शीर्ष अदालत के निर्देशों का ही उल्लंघन करते रहे हैं। बाबा के आयुर्वेद बनाम एलोपैथी की यह लड़ाई, 'इंडियन मेडिकल एसोसिएशन' के जरिए, बीते दो सालों से सर्वोच्च अदालत के विचाराधीन है। अब बात बाबा के माफीनामे से भी आगे निकल चुकी है। मौजूदा दौर जीवन-शैली के रोगों का है, लिहाजा योग, आयुर्वेद, शरीर को विष-मुक्त करना और हर्बल थेरेपी आदि ज्यादा लोकप्रिय हैं। लोग उनके जरिए स्वास्थ्य-लाभ पा रहे हैं। देश की मोदी सरकार ने भी आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी, योग और सिद्ध आदि चिकित्सा प्रणालियों का एक ही मंत्रालय-आयुष-में विलय कर दिया है। 'जन औषधि केंद्रों' के जरिए जेनरिक दवाएं भी लोगों को उपलब्ध कराई जा रही हैं। बेशक स्वास्थ्य की देखभाल में इन प्राचीन चिकित्सा प्रणालियों की अपनी महत्वपूर्ण भूमिका रही है, लेकिन बाबा जैसे पैरोकार आधुनिक चिकित्सा प्रणाली 'एलोपैथी' को गालियां देते हुए अथवा जहर बेचने वाले करार देकर अपने 'आयुर्वेद' को नहीं बेच सकते।

जिस देश में नीमहकीमी और विज्ञान-विरोधी मानसिकता अनियंत्रित हो, उसमें नियामक प्रोटोकॉल से कोई भी समझौता नहीं किया जा सकता। नियामक संस्थाएं पतंजलि की औषधियों की जांच करें। यह उनका संवैधानिक अधिकार भी है। जांच की प्रक्रिया के बाद अपने निष्कर्ष देश के सामने रखें कि पतंजलि की दवाओं का सच क्या है? बाबा रामदेव देश, उसके संविधान और कानून से ऊपर नहीं हो सकते। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के दौरान भी बाबा ने लोगों की चिंताओं से खिलवाड़ किया और कई गलत दावे किए। उनकी भी सम्यक जांच होनी चाहिए। सर्वोच्च अदालत में सुनवाई के दौरान पतंजलि को खूब फटकार भी लगाई गई है। बाबा रामदेव ने फार्मा और मेडिकल इंडस्ट्री की गलत धारणाओं से बचने की चेतावनी देश को दी थी और यहां तक आरोप लगाए थे कि ये जहर बेच रहे हैं, लिहाजा खुद को बचाओ। बाबा ऐसी टिप्पणियां किस आधार पर कर सकते हैं? यदि शरीर के भीतर किसी रोग की गहराई तक पहुंचना है, तो उसके लिए आधुनिक चिकित्सा प्रणाली में अनेक अनुसंधान किए गए हैं।

राय

मोदी बनाम सुक्खू

हिमाचल में चुनावी बिसात पर इस बार नए दांव पेंच के अलावा केंद्र बनाम राज्य की सीधी टक्कर होने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर शतरंज के माहिर खिलाड़ी हैं, तो मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू भी सियासी खेल के उस्ताद तो तसदीक हो चुके हैं। उनके प्रशंसक तथा आलाकमान तक उनके समर्थक यह मानते हैं कि इस बंदे में इतना दम तो है कि यह वीरभद्र सिंह द्वारा बिछाई तमाम सुरंगों तथा दीवारों को लांघ कर स्वीकार्य नेता साबित हुए। सत्ता से पहले संगठन की ताकत में सुक्खू ने अपना जौहर दिखाकर कई किले छीने हैं, लेकिन अब सरकार के दुर्ग को बचाने का इम्तिहान है। बहरहाल हिमाचल में लोकसभा के साथ उपचुनावों का जुडऩा, कहीं तो प्रदेश सरकार की नीति और नीयत को अखाड़े तक ले आया है। हमने इन्हीं कालमों में मुख्यमंत्री के प्रदर्शन का सदैव दो पहलुओं में विश्लेषण किया है। वह राजनीति के माहिर रहे हैं। वह राजनीति को चलाने का माद्दा व इरादा भी बेहतर रखते हैं, लेकिन सरकार के बीच राजनीति और राजनीति के बीच सरकार को पूर्ण सुरक्षित सांचे में रखने के लिए संतुलन नहीं बना सके।

जब सुक्खू सरकार बनी तो मुख्यमंत्री के पक्ष में आस्था के 43 दीप जले थे, जो अब घटकर 34 हो चुके हैं। इसमें दो राय नहीं कि 34 की संख्या को आसानी से 36 या 37 विधायकों तक पहुंचाया जा सकता है, लेकिन बतौर मुख्यमंत्री ऐसी परिस्थिति तक पहुंचना प्रदेश की पूरी राजनीति के लिए घातक है। यहां उनके सवा साल के सफर में मुख्यमंत्री का पद, प्रदेश का शासन तंत्र, प्रशासनिक पकड़, चुनौतियों की राह और पहाड़ी प्रदेश की दुश्वारियों का उल्लेख भी हो रहा है। जाहिर तौर पर सरकार का कद विभिन्न मोर्चों पर दिखाई दिया और व्यवस्था परिवर्तन के मार्गदर्शन पर हिमाचल का नजरिया बदलता हुआ महसूस हुआ। ऐसे में चुनावी दौड़ में हिमाचल अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इतिहास से प्रभावित रहेगा, तो सुक्खू के व्यक्तित्व की धार से भी संबोधित होगा। कम से कम हिमाचल में मोदी को सीधे सुक्खू से टकराना पड़ेगा।

इसे हम एक दृष्टि से सुक्खू की बतौर मुख्यमंत्री उपलब्धि तो मान ही सकते हैं, लेकिन दूसरी ओर राजनीतिक घटनाक्रम के अवांछित अध्याय अशांत और रूठे हुए बैठे हैं। कुछ दरारें अब दीवारें बन गईं, लेकिन जमीन का धंसना नहीं रुका। इसमें कोई दो राय नहीं कि सवा साल के परिश्रम में सुक्खू सरकार का आपदा प्रबंधन पूरे देश ने देखा है और जहां केंद्र बनाम हिमाचल के बीच अधिकारों का आमना-सामना भी मुख्यमंत्री को सशक्त बनाता रहा। प्रशासनिक तौर पर कई फैसले सही होंगे, तो कई अन्य नापसंद भी किए गए, लेकिन भूराजस्व महकमे के नजरिए में परिवर्तन लाकर मुख्यमंत्री का रुतबा लोगों का दिल जीत लेता है। जमीनी दस्तावेजों में लंबित इंतकाल और तकसीम मामलों को सुलझाने का रिकार्ड कायम करके साबित कर दिया कि सरकार अगर चाहे तो व्यवस्था परिवर्तन ला सकती है। सुक्खू ने सरकार में अपने हस्ताक्षर प्रशासनिक तौर पर तो सशक्त किए, लेकिन राजनीतिक तौर पर इसकी कीमत तय है। कुछ चुकानी पड़ी, लेकिन कसरतों में अगर वह सफल होते हैं, तो इतिहास उनके साथ खड़ा होगा। कम से कम यह तो आज ही कहा जा सकता है कि हिमाचल में लोकसभा से उपचुनावों तक सुक्खू बनाम मोदी होने जा रहा है। अगर डबल इंजन सरकार का नारा लगा, तो हिमाचली अधिकार तथा आपदा में केंद्र की बेरुखी पर सवाल उठेंगे और अगर केंद्रीय योजनाएं सामने रखी गईं, तो ओपीएस लागू करके सुक्खू आगे खड़े हो जाएंगे। मुकाबले फोरलेन व रेलवे विस्तार की आंखों में आंखें डाल कर वंदे भारत की यात्रा कराएंगे, तब सुक्खू के पैमाने कांगड़ा एयरपोर्ट विस्तार तथा पर्यटन राजधानी तक उतर आएंगे।

भूपिंदर सिंह

विद्यार्थियों के लिए फिटनेस कार्यक्रम जरूरी

कम से कम बीस मिनटों तक तेज चलने, दौडऩे व शारीरिक क्रियाओं के करने से रक्त वाहिकाओं में रक्त संचार तेज हो जाता है। उससे हर मसल को उपयुक्त मात्रा में प्राणवायु मिलने से उसका समुचित विकास होता है। आज के विद्यार्थी को अगर कल का अच्छा नागरिक बनाना है तो हमें उसके लिए सही फिटनेस कार्यक्रम भी देना होगा'

वर्षों से स्कूली स्तर पर फिटनेस कार्यक्रम शुरू करने की बात इस कॉलम के माध्यम से हो रही है, मगर हिमाचल प्रदेश का कोई भी सरकारी या निजी स्कूल अपने यहां फिटनेस कार्यक्रम लागू करने में नाकाम रहा है। कई बार नए शिक्षा सत्र शुरू होकर खत्म हो गए, मगर फिटनेस कार्यक्रम कहीं भी शुरू नहीं हो पाया है। मगर इस वर्ष हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य के विद्यालयों में विद्यार्थियों की सामान्य फिटनेस के लिए पहले की तरह अनिवार्य रूप से ड्रिल के पीरियड का प्रावधान किया है। शिक्षण विषयों के रिपोर्ट कार्ड की तरह स्वास्थ्य के मानकों का रिपोर्ट कार्ड भी प्रत्येक विद्यार्थी का हर स्कूल में अनिवार्य रूप से हो, क्योंकि भाषा व अन्य शिक्षण विषयों की तरह ही स्वास्थ्य के मूल स्तंभ स्पीड, सट्रेंथ, इडोरैंस व लचक आदि का प्रायोगिक प्रशिक्षण भी उसी उम्र में शुरू करना होता है। शिक्षण विषयों के लिए तो स्कूलों के पास शिक्षक सहित पूरा प्रबंध है, मगर स्वास्थ्य के घटकों को विकसित करके उनका मूल्यांकन करने की कोई भी सुविधा आज तक उपलब्ध नहीं हो पाई है। इस कॉलम के माध्यम से कई बार इस विषय पर स्कूलों व अभिभावकों को चेताया जा चुका है, मगर कोई भी समझने के लिए तैयार नहीं है।

किसी भी देश को इतनी क्षति युद्ध या महामारी से नहीं होती है, जितनी तबाही नशे के कारण हो सकती है। आज जब देश के अन्य राज्यों सहित हिमाचल प्रदेश में भी नशा युवा वर्ग पर ही नहीं किशोरों तक चरस, अफीम, स्मैक, नशीली दवाओं तथा दूरसंचार के माध्यमों के दुरुपयोग से शिकंजा कस रहा है, इसलिए सरकार, स्कूल प्रबंधन व अभिभावकों को इस विषय पर जरूरी कदम जल्दी ही उठा लेने चाहिएं। यदि विद्यार्थी किशोरावस्था में नशे से बच जाता है तो वह फिर युवावस्था आते-आते समझदार हो गया होता है। माध्यमिक से वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय स्तर पर विद्यार्थियों को विभिन्न विधाओं में व्यस्त रखने के साथ-साथ शारीरिक फिटनेस की तरफ मोडऩा बेहद जरूरी हो जाता है। मानव का सर्वांगीण विकास शिक्षा के बिना अधूरा है। शिक्षा की परिभाषा में साफ-साफ लिखा है कि यहां शारीरिक व मानसिक दोनों तरह से बराबर विद्यार्थियों का विकास करना है जिससे वे आगे चलकर जीवन को सफलतापूर्वक खुशहाल जी सकें। शारीरिक विकास के लिए खेलों के माध्यम से फिटनेस कार्यक्रम बहुत जरूरी हो जाता है। खेल ही वह माध्यम है जिसके द्वारा विद्यार्थी को नशे से दूर रखा जा सकता है। पड़ोसी राज्य पंजाब एक समय तरक्की में देश का अग्रणी राज्य रहा है। खेलों में उत्कृष्टता उस प्रदेश की तरक्की व खुशहाली का भी पैमाना होती है। पंजाब में हजारों प्रशिक्षक विभिन्न खेलों में खेल प्रशिक्षण के लिए नियुक्त होने के साथ-साथ खेल प्रशिक्षण के लिए आधारभूत ढांचा होना वहां के विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास का प्रमुख कारण रहा था। बाद में जब पंजाब धीरे-धीरे खेलों से दूर हुआ तो पहले वहां आतंकवाद और फिर आजकल पंजाब नशे का अड्डा बना हुआ है। यही कारण है कि हर क्षेत्र में आज हरियाणा पंजाब से काफी आगे निकल गया है।

पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एशियाई, राष्ट्रमंडल व ओलंपिक खेलों में पदक विजेता होने पर खिलाडियों को करोड़ों रुपए के नगद ईनाम व सम्मानजनक नौकरी देकर हरियाणा में खेलों के लिए बहुत ही उपयुक्त वातावरण

तैयार किया है। उसी का नतीजा है कि आज हरियाणा का हर किशोर व युवा किसी न किसी खेल के मैदान में नजर आता है। हिमाचल प्रदेश में भी पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने प्रदेश की खेलों के लिए अपने पहले कार्यकाल से ही कई महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए हिमाचल प्रदेश में कई खेलों के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्ले फील्ड, सरकारी नौकरियों में तीन प्रतिशत आरक्षण तथा देश में प्रशिक्षक कैडर डाईंग हो जाने के बाद पहली बार प्रशिक्षकों की भर्ती जैसे बहुत बड़े खेल सुधार किए। हिमाचल प्रदेश की खेल सुविधाओं का प्रयोग राज्य में स्वास्थ्य व खेलों के लिए बड़े स्तर पर करना चाहिए। हिमाचल प्रदेश इस समय शिक्षा के क्षेत्र में देश के अग्रणी राज्यों में गिना जाता है। पिछले कुछ दशकों से हिमाचल प्रदेश के नागरिकों की फिटनेस में बहुत कमी आई है। इसका प्रमुख कारण विद्यालय स्तर पर विद्यार्थियों के लिए किसी भी प्रकार के फिटनेस कार्यक्रम का न होना है। रट्टे वाली पढ़ाई की होड़ में हम विद्यार्थियों की फिटनेस को ही भूल गए हैं। हिमाचल प्रदेश की अधिकांश आबादी गांव में रहती थी। वहां पर सवेरे-शाम वर्षों पहले विद्यार्थी अपने अभिभावकों के साथ कृषि व अन्य घरेलू कार्यों में सहायता करते थे। छात्र विद्यालय आने-जाने के लिए कई किलोमीटर दिन में पैदल चलता था। इसलिए उस समय के विद्यार्थी को किसी भी प्रकार के फिटनेस कार्यक्रम की कोई जरूरत नहीं थी। आज का विद्यार्थी घर के आंगन में बस पर सवार होकर विद्यालय के प्रांगण में उतरता है। पढ़ाई के नाम पर ज्यादा समय खर्च करने के कारण फिटनेस के लिए कोई समय नहीं बचता है। अधिकांश स्कूलों के पास फिटनेस के लिए न तो आधारभूत ढांचा है और न ही कोई कार्यक्रम है। आज का विद्यार्थी फिटनेस व मनोरंजन के नाम पर दूरसंचार माध्यमों का कमरे में बैठ कर खूब दुरुपयोग कर रहा है। ऐसे में विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास की बात मजाक लगती है। आज के विद्यार्थी के लिए विद्यालय या घर पर आधे घंटे के फिटनेस कार्यक्रम की सख्त जरूरत है। इसमें 15 से 20 मिनट धीरे-धीरे दौडऩा तथा विभिन्न कोणों पर शरीर के जोड़ों की विभिन्न क्रियाओं को पूरा करने के बाद शरीर को कूलडाऊन करना होगा। कम से कम बीस मिनटों तक तेज चलने, दौडऩे व शारीरिक क्रियाओं के करने से रक्त वाहिकाओं में रक्त संचार तेज हो जाता है। उससे हर मसल को उपयुक्त मात्रा में प्राणवायु मिलने से उसका समुचित विकास होता है। आज के विद्यार्थी को अगर कल का अच्छा नागरिक बनाना है तो हमें स्कूली पाठ्यक्रम में पढ़ाई के साथ-साथ उसके लिए सही फिटनेस कार्यक्रम भी देना होगा। तभी हम सही अर्थों में अपनी अगली पीढ़ी को संपूर्ण शिक्षित कर सकते हैं।

सुरेश सेठ

छिलकों की छाबड़ी : बाल पुराण!

मैं बालों की समस्या से परेशान हो गया हूं। इधर बीस वर्ष पूर्व मेरे बाल काले हुआ करते थे। इधर अब हाल यह हो गया है कि सिर के बाल काले और सफेद मिलकर अजीब तरह की खिचड़ी बन गए हैं। दाढ़ी की सफेदी को तो मैंने रोज शेव बनाकर सलटा दिया है, परंतु ये सिर के बाल मेरी पोल खोलने पर तुले हुए हैं। पत्नी और बच्चे सदैव यह कहते रहते हैं कि मैं समय रहते इनका कोई स्थायी समाधान निकालूं, परंतु मेरा दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा। इन बालों की वजह से मेरा चेहरा भी बदल गया है। उम्र ने तो खैर चेहरे का भूगोल बदला ही है, रही-सही कसर बालों ने पूरी कर दी है। बाल भी सख्त होकर खड़े हो गए हैं तथा उनका रेशमीपन जाता रहा है। इस पचपन वर्ष की उम्र ने मुझे लगभग जोकर सा बना दिया है। मेरे बालों को लेकर डॉक्टरों ने तो अपने हाथ खड़े कर दिए हैं, परंतु टीवी पर आने वाले साबुनों, शैम्पुओं तथा डाइयों के विज्ञापनों ने मुझ में एक उम्मीद अवश्य जगा रखी है। बाल तो बदरंग हुए ही, मुझे जबरदस्त डैंड्रूफ का रोग अलग से है। हमेशा बालों के ऊपर एक गर्द सी छाई रहती है। पत्नी ने अवश्य पचास की होने के बावजूद अपने बालों को मेनटेन कर रखा है। पता नहीं दिनभर क्या-क्या उपाय करती है, जिससे उसके बाल रेशमी, मुलायम, काले और आकर्षक हैं। हालांकि यह कार्य काफी व्ययसाध्य हो रहा है, परंतु स्टेटस के लिए पत्नी को आकर्षक बनाए रखना आज की महती आवश्यकता भी है। मेरे खिचड़ी और भद्दे बालों के कारण वह बाजार, पार्टी अथवा किसी समारोह में न तो मेरे साथ जा पाती है और न अपने साथ मुझे ले जा पाती है।

अजीब सी ऊहापोह बन गए हैं मेरे सिर के बाल। विज्ञापनों में आने वाले साबुन, शैम्पू, तेल और डाई रोगन इतने प्रकार के हैं कि तय करना मुश्किल है कि कौनसा साधन सस्ता, टिकाऊ और आकर्षक रहेगा। किसी में क्या विशेषता है तो किसी में क्या कमी है, इस चक्कर में कोई सर्वमान्य निर्णय नहीं कर पा रहा हूं। बच्चों का तो सुझाव यह है कि मैं बालों में कलर करवाकर इस समस्या को ढक सकता हूं, लेकिन पत्नी कहती है कि पहले बालों को ऐसा पोषण दो ताकि ये शूल की तरह खड़ा रहना बंद करें। जब पोषण से ये सतह पर आ जाएं तो इन्हें खूबसूरती से काला करो। मैंने पत्नी को समझाया भी कि जब ये काले थे, तब चेहरे का काला रंग और इनका काला रंग मिलकर क्या गुल खिला रहे थे, इससे तुम अनभिज्ञ नहीं हो। इसलिए बच्चों का कलरिंग वाला आइडिया उचित रहेगा, लेकिन पता नहीं वह क्यों बालों को काला करवाने पर तुली है। मेरे ये बाल अनचाहे बाल बन गए हैं, इस तरह मैं अनचाहे बालों की समस्या से ग्रस्त हूं। एक दिन मैंने विशुद्ध मेहंदी का प्रयोग कर उन्हें नए रूप में देखना चाहा तो वे और अधिक भयावह बन गए। पत्नी ने उसी दिन कहा काली मेहंदी लगाकर और देख लो, यदि ये लुभावने हो जाते हैं तो ठीक है, वरना अपन कोई और आयुर्वेदिक उपाय खोजेंगे। मैंने काली मेहंदी लगाई तो जिसका डर था, वही हुआ, मैं लगभग लंगूर जैसा बन गया। बच्चे हंसने लगे। पत्नी ने उन्हें इस बदतमीजी के लिए डांटा और मुझे आंवला, अरीठा तथा दही से बाल धोने का नुस्खा दिया। मैंने कहा, खाने को दही मिलता नहीं और बालों को दही से सींचो, कितनी असंगत बात है। लेकिन पत्नी के कथन की अनदेखी भी नहीं की जा सकती थी। अतः दो माह तक शीतकाल में मैंने आंवला, अरीठा और दही का प्रयोग किया तो मेरे ठंड ऐसी जमी कि इस उपचार को बंद करके, मैं डॉक्टर की तरफ कफ-खांसी और ज्वर की दवा लेने दौड़ा। दफ्तर से छुट्टी ली, वह अलग थी।

इनसाइड

150 रुपये गिरा सोने का भाव, क्या कीमतों और आएगी गिरावट?

एक दिन पहले 70050 रुपये प्रति 10 ग्राम का सर्वकालिक स्तर छूने के बाद सोने की कीमतों 150 रुपये की गिरावट आई है। दिल्ली में 10 ग्राम सोने का भाव 69900 रुपये दर्ज किया गया। HDFC सिक्योरिटीज के मुताबिक ग्लोबल मार्केट में महंगी धातुओं का भाव गिरा है जिसका असर भारतीय बाजार पर भी दिखा। आइए जानते हैं पूरी खबर।

नई दिल्ली। अपने ऑलटाइम हाई लेवल पर पहुंचने के बाद सोने की कीमतों (gold price) में 150 रुपये की गिरावट आई है और यह राष्ट्रीय राजधानी में 69,900 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर आ गया। HDFC सिक्योरिटीज के मुताबिक, ग्लोबल मार्केट में महंगी धातुओं का भाव गिरा है, जिसका असर भारतीय बाजार पर भी दिखा।

पिछले कारोबारी सत्र में पीली धातु 70,050 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गई थी। इसने पहली बार 70 हजार रुपये का स्तर पार किया था। वहीं, चांदी की बात करें, तो इसमें 700 रुपये की गिरावट आई और यह 81,000 रुपये प्रति किलो के स्तर पर बंद हुई।

हालांकि, एक्सपर्ट का मानना है कि इस मामूली गिरावट के बावजूद सोने में तेजी का रुख बना रहेगा। LKP सिक्योरिटीज में रिसर्च एनालिस्ट जतिन त्रिवेदी का कहना है कि जब तक मध्यपूर्व में भू-राजनीतिक तनाव और ब्याज दरों में कटौती की उम्मीदें बनी रहेंगी, तब तक सोने में तेजी का रुझान रहेगा।

दुनियाभर के केंद्रीय बैंक भी सोने की खरीद पर जोर दे रहे हैं, ताकि अचानक आने वाले आर्थिक संकट के नुकसान को कम से कम कर सकें। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास का भी कहना है कि रिजर्व बैंक अपने विदेशी मुद्रा भंडार को मजबूत करने के लिए सोने की खरीद बढ़ाएगा।

ऑफिशियल डेटा के मुताबिक, 22 मार्च को विदेशी मुद्रा भंडार में सोने की वैल्यू 51.48 अरब डॉलर थी। यह मार्च 2023 के मुकाबले 6.28 अरब डॉलर अधिक है। आरबीआई ने अकेले जनवरी में 8.7 टन सोना खरीदा, जो पिछले दो साल में सबसे ज्यादा है।

हालांकि, गोल्ड की ऊंची कीमतों के चलते आम खरीदार फिलहाल इससे दूरी बना रहे हैं। अभी वही लोग गहने-जेवरात खरीद रहे हैं, जिनके घर में शादियां हैं। बाकी लोगों ने खरीदारी या तो कम कर दी है, या फिर कुछ समय के लिए टाल दी है।

सीडीएम में नकद भी जमा कर सकेंगे यूपीआई से, प्रीपेड कार्ड का यूपीआई भुगतान अन्य एप से भी

कुछ महीने पहले तक यूपीआई से सिर्फ पेमेंट किया जा सकता था लेकिन अब इसके इस्तेमाल से एटीएम से बिना डेबिट कार्ड के कैश भी निकाला जा सकता है। लेकिन आने वाले महीनों में यूपीआई की मदद से कैश डिपॉजिट मशीन (सीडीएम) में नकद जमा भी कर सकेंगे। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने यह जानकारी दी है।

परिवहन विशेष न्यूज

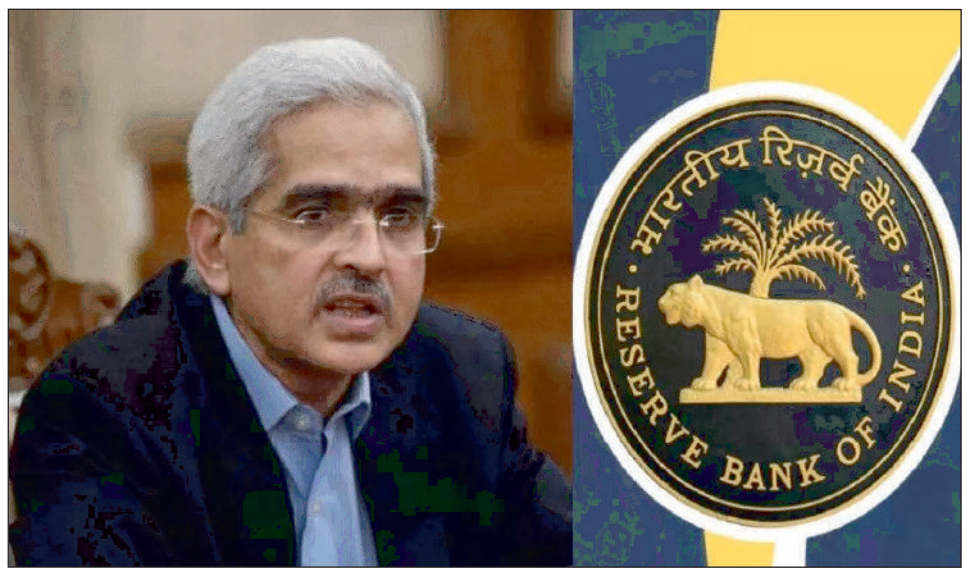

नई दिल्ली। कुछ माह पहले तक यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआई) की मदद से सिर्फ भुगतान किया जा सकता था। अब यूपीआई का इस्तेमाल कर एटीएम से बिना डेबिट कार्ड के नकदी भी निकाली जा सकती हैं। लेकिन आने वाले महीनों में यूपीआई की मदद से कैश डिपॉजिट मशीन (सीडीएम) में नकद जमा भी कर सकेंगे।

शुक्रवार को आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि बिना किसी कार्ड के एटीएम से नकद निकासी के अनुभव को देखते हुए अब यूपीआई से नकद जमा शुरू करने का प्रस्ताव लाया गया है। इससे ग्राहकों के साथ बैंकों को भी सुविधा होगी। आरबीआई इस नए प्रस्ताव के लागू होने का विस्तृत ब्योरा कुछ दिनों में घोषित करेगा।

दास ने यूपीआई यूजर्स की सुविधा के लिए एक और घोषणा की। प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट (पीपीआई) इस्तेमाल करने वाले यूजर्स अब किसी अन्य ऐप से जुड़कर भी यूपीआई भुगतान कर सकेंगे। अभी पीपीआई रखने वाले यूजर्स यूपीआई भुगतान सिर्फ उस पीपीआई के एप से कर सकते हैं। मुख्य रूप से ई-गिफ्ट कार्ड या मोबाइल वॉलेट को पीपीआई माना जाता है।

अभी अगर किसी के पास प्लक्सी इंडिया का प्रीपेड कार्ड है तो उस कार्ड में जमा रकम से खरीदारी करने के लिए या तो ग्राहक को कार्ड अपने साथ रखना होगा या फिर प्लक्सी इंडिया के एप पर जाकर यूपीआई से उसका भुगतान करना होगा। प्रस्तावित नियम के मुताबिक यूजर्स प्रीपेड कार्ड को गूगल पे, फोन पे जैसे ऐप से जोड़ कर भुगतान कर सकेगा।

आरबीआई ने नान बैंक पेमेंट सिस्टम के जरिए सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (सीबीडीसी) या ई-रुपए को मुहैया कराने का भी फैसला किया है। गूगल पे, फोन पे, पेटीएम जैसे नान बैंक पेमेंट सिस्टम या थर्ड पार्टी एप अब ग्राहकों को ई-रुपए मुहैया करा सकेंगे ताकि ई-रुपए का चलन बढ़ सके। अभी सिर्फ बैंक से ही ई-रुपये मिल सकते हैं।

इस बारे में विस्तृत निर्देश बाद में जारी होगा। सरकारी प्रतिभूति खरीदने वाले खुदरा निवेशकों की सुविधा के लिए आरबीआइ ने मोबाइल एप लाने का भी फैसला किया है। रिन्यूएबल परियोजनाओं की वित्तीय व्यवस्था के लिए इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर (आईएफएससी) के माध्यम से ग्रीन बांड भी लाया जाएगा। इसके बारे में जल्द ही अधिसूचना जारी की जाएगी।

RBI ने IDFC फर्स्ट बैंक और LIC हाउसिंग फाइनेंस पर लगाया जुर्माना, जानें क्या है वजह

रिजर्व बैंक (RBI) ने IDFC फर्स्ट बैंक पर 1 करोड़ रुपये और LIC हाउसिंग फाइनेंस पर 49 .70 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। केंद्रीय बैंक ने बताया कि इन दोनों वित्तीय संस्थानों ने नियमों की अनदेखी की है। IDFC फर्स्ट बैंक पर जुर्माना 2016 और 2017 में एक सरकारी कंपनी को इंफ्रास्ट्रक्चर लोन देने के मामले में लगाया है। आइए जानते हैं पूरी खबर।

मुंबई। रिजर्व बैंक (RBI) ने IDFC फर्स्ट बैंक पर 1 करोड़ रुपये और LIC हाउसिंग फाइनेंस पर 49.70 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। केंद्रीय बैंक ने बताया कि इन दोनों वित्तीय संस्थानों ने नियमों की अनदेखी की है।

क्यों लगा जुर्माना?

RBI ने एक बयान में कहा कि उसने प्राइवेट सेक्टर के IDFC फर्स्ट बैंक पर जुर्माना 2016 और 2017 में एक सरकारी कंपनी को इंफ्रास्ट्रक्चर लोन देने के मामले में लगाया है। इसमें 'Loans and Advances - Statutory and Other Restrictions' पर केंद्रीय बैंक के निर्देशों का पालन नहीं किया गया।

RBI ने 31 मार्च, 2022 तक बैंक की वित्तीय स्थिति की जांच की। इसमें पता चला कि बैंक ने दिशा-निर्देशों का पालन नहीं किया है। ऐसे में बैंक को RBI ने नोटिस जारी किया और जवाब से संतुष्ट ना होने के बाद जुर्माना लगाया।

वहीं, LIC हाउसिंग फाइनेंस पर जुर्माना RBI के 'नॉन-बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज-हाउसिंग फाइनेंस कंपनी (रिजर्व बैंक) गाइडलाइंस, 2021' के कुछ प्रावधानों का पालन नहीं करने की वजह से लगा है।

क्या ग्राहकों पर होगा असर?

दोनों ही वित्तीय संस्थानों पर एक्शन नियमों का सही तरीके से पालन नहीं करने की वजह से लिया गया है। ऐसे में इसका ग्राहकों के साथ किसी भी लेनदेन या समझौते पर कोई असर नहीं होगा। अगर जुर्माना लगाने के अलावा भी आरबीआई दोनों संस्थाओं के खिलाफ कोई एक्शन लेता है, तो उसका ग्राहकों के हितों पर कोई असर नहीं होगा।

चार NBFC पर भी गिरी गाज

आरबीआई ने चार NBFC- कुंडल्स मोटर फाइनेंस, नित्या फाइनेंस, भाटिया हायर परचेज और जीवनज्योति डिपॉजिट्स एंड एडवांसेज का सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन (CoR) भी रद्द कर दिया है। ये चारों कंपनियां अब बतौर नॉन-बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कोई कारोबार नहीं कर सकतीं।

दिल टूटने का दर्द समझ रही ये फिनेटक कंपनी, उबरने के लिए देगी एक हफ्ते की छुट्टी

फिनटेक कंपनी StockGro ने अपनी लीव पॉलिसी अपडेट की है। कंपनी रिश्तों में अलगाव से गुजर रहे कर्मचारियों को उबरने के लिए एक हफ्ते की छुट्टी दे रही है। कंपनी का कहना है कि इस छुट्टी के लिए कर्मचारी से किसी तरह के सवाल जवाब नहीं किए जाएंगे। इसके साथ ही उन्हें इसके लिए किसी तरह का सबूत भी नहीं देना होगा।

बेंगलुरु। फिनटेक कंपनी StockGro ने अपनी लीव पॉलिसी अपडेट करते हुए अनूठी मिसाल पेश की है। कंपनी रिश्तों में अलगाव से गुजर रहे कर्मचारियों के लिए ब्रेक-अप लीव (Break-Up Leave) पॉलिसी लेकर आई है। कंपनी का कहना है कि यह पॉलिसी उनके कर्मचारियों के प्रति समझ और गहरी देखभाल को दिखाता है, जो उनकी प्रोफेशनल लाइफ से इतर उन्हें सपोर्ट देने के लिए उठाया गया है।

ब्रेकअप लीव पॉलिसी को लेकर स्टॉकग्रो ने बताया कि यह बदलाव का समय है। हम अपनी टीम को परिवार के रूप में देखते हैं। कर्मचारियों के निजी जीवन में उथल-पुथल के समय हम उनके साथ मौजूद रहना चाहते हैं। ब्रेक-अप लीव के जरिए हम उन्हें सपोर्ट देना चाहते हैं। फाउंडर अजय लखोटिया ने कहा कि हम जानते हैं कि अलगाव के दौरान अपने लिए वक्त निकलना बेहतर रहता है।

StockGro की ब्रेक-अप पॉलिसी

नई लीव पॉलिसी के तहत, कंपनी का कोई भी कर्मचारी रिश्ते में अलगाव के बाद एक हफ्ते की छुट्टी ले सकता है। इस छुट्टी के लिए उससे किसी तरह के सवाल नहीं किए जाएंगे।

कंपनी का कहना है कि इस लीव पॉलिसी से वह अपने कर्मचारियों के दिल टूटने, उदासी और मन में चल रही उधेड़बुन के दौरान उन्हें शांति और राहत देना चाहती है। इसके साथ कर्मचारी चाहे तो वह मैनेजमेंट के साथ बात कर अपनी छुट्टी आगे बढ़ा सकता है।

स्टॉकग्रो ने बताया कि कर्मचारी को इस लीव के लिए किसी तरह के सबूत देने की जरूरत नहीं होगी।

क्या करती है स्टॉकग्रो?

StockGro भारत की प्रीमियम फिनटेक स्टार्टअप है जो यूजर्स को ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट की जानकारी देने के लिए प्लेटफॉर्म मुहैया करता है। कंपनी के 30 मिलियन यूजर्स हैं।

सोने का भंडार बढ़ा रहा रिजर्व बैंक, किस संकट से निपटने की हो रही तैयारी?

RBI गवर्नर शक्तिकांत दास का कहना है कि भारत अपने सोने के भंडार को बढ़ा रहा है। दुनिया के कई देशों में मंदी आने की आशंका और बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव से आर्थिक संकट गहराने के आसार हैं। यही वजह है कि दुनियाभर के केंद्रीय बैंक अपना गोल्ड रिजर्व बढ़ा रहे हैं। आइए जानते हैं कि भारत के पास कितना गोल्ड है।

नई दिल्ली। कई देशों में आर्थिक मंदी की आशंका और बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव के बीच दुनियाभर के केंद्रीय बैंक अपना गोल्ड रिजर्व (gold reserves) बढ़ा रहे हैं। इसमें भारत का रिजर्व बैंक (RBI) भी शामिल हो गया है।

RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास (Shaktikanta Das) ने शुक्रवार को कहा कि भारत अपने विदेशी मुद्रा भंडार को मजबूत करने के लिए गोल्ड रिजर्व यानी सोने का भंडार बढ़ा रहा है।

शक्तिकांत दास ने पॉलिसी रिव्यू के बाद रिपोर्टर्स से बात कर रहे थे। हालांकि, उन्होंने कोई आधिकारिक आंकड़ा नहीं बताया, जिससे पता चले कि गोल्ड रिजर्व की वैल्यू में कितना इजाफा हुआ है।

ऑफिशियल डेटा के मुताबिक, 22 मार्च को विदेशी मुद्रा भंडार में सोने की वैल्यू 51.48 अरब डॉलर थी। यह मार्च 2023 के मुकाबले 6.28 अरब डॉलर अधिक है।

RBI ने कितना सोना खरीदा?

पिछले दिनों की एक न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक, आरबीआई ने अकेले जनवरी में 8.7 टन सोना खरीदा, जो दो साल में सबसे ज्यादा है। वहीं वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के अनुसार, केंद्रीय बैंक की सोने की होल्डिंग जनवरी के अंत में 812.3 टन तक पहुंच गई थी, जो उससे पिछले महीने में 803.58 टन थी।

पिछले कुछ महीनों में सोने की कीमत में भी तेजी देखी गई है। इससे आम उपभोक्ताओं ने गहने-जेवरात की खरीदारी कम कर दी है या फिर कुछ वक्त के लिए टाल दी है। सोने के भाव में भारी इजाफे की एक वजह केंद्रीय बैंकों की खरीद को भी बताया जा रहा है।

क्यों ज्यादा सोना खरीदा रहा RBI?

दास ने यह भी बताया कि कुल विदेशी मुद्रा भंडार 29 मार्च तक 645.6 अरब डॉलर के सर्वकालिक उच्च स्तर तक पहुंच गया। उन्होंने कहा कि RBI ने पिछले चार-पांच वर्षों में जानबूझकर विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ाने पर फोकस किया है, ताकि अचानक आने वाले बड़े आर्थिक संकट से निपटा जा सके।

दास ने यह भी कहा कि विदेशी मुद्रा के मोर्चे पर केंद्रीय बैंक का नजरिया नेशनल बैलेंस शीट को भी मजबूती देता है। दास ने रुपये को मजबूत करने पर भी बात की। उन्होंने कहा कि रुपये को स्थिर करना रिजर्व बैंक की प्राथमिकता सूची में शामिल है।

महंगाई का 'हाथी' काबू में, सस्ते कर्ज के लिए अभी करना होगा इंतजार

एमपीसी की बैठक हर दो महीनों पर होती है और यह इस समिति की सातवीं बैठक है जिसमें रेपो रेट को उसके मौजूद दर 6.5 फीसद पर ही बना कर रखने का फैसला किया है। पिछले एक वर्ष से खुदरा महंगाई की दर तकरीबन छह फीसद या इससे नीचे ही हैं। आरबीआइ इसे चार फीसद पर लाने की कोशिश में है।

नई दिल्ली। आम ग्राहकों को होम लोन, ऑटो लोन व दूसरे बैंकिंग कर्ज के सस्ता होने के लिए अभी और इंतजार करना पड़ेगा। शुक्रवार को मौद्रिक नीति की समीक्षा करने वाली समिति ने इन दरों को प्रभावित करने वाले रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं करने का फैसला किया है। आरबीआइ गवर्नर डॉ. शक्तिकांत दास ने हालांकि लंबे समय के बाद यह कहा है कि महंगाई रूपी हाथी अब काबू में है।

साल के आखिर में कम हो सकता है रेपो रेट

उन्होंने चालू वित्त वर्ष 2024-25 के लिए खुदरा महंगाई दर (सीपीआइ) के सालाना लक्ष्य को घटा कर 4.5 फीसद पर कर दिया है। जबकि देश की अर्थव्यवस्था में 7 फीसद की वृद्धि दर का अनुमान लगाया है। ऐसा हुआ तो भारत लगातार चौथे वर्ष सात फीसद से ज्यादा की आर्थिक वृद्धि दर हासिल करेगा। उम्मीद की जा सकती है कि सब कुछ सामान्य रहा तो इस साल के अंतिम महीनों में रेपो रेट को घटा कर आम जनता व उद्योग जगत के लिए सस्ते कर्ज का रास्ता साफ हो सकता है।

लगातार सातवीं बार रेपो रेट में नहीं हुआ बदलाव

एमपीसी की बैठक हर दो महीनों पर होती है और यह इस समिति की सातवीं बैठक है जिसमें रेपो रेट को उसके मौजूद दर 6.5 फीसद पर ही बना कर रखने का फैसला किया है। पिछले एक वर्ष से खुदरा महंगाई की दर तकरीबन छह फीसद या इससे नीचे ही हैं। आरबीआइ इसे चार फीसद पर लाने की कोशिश में है। दो वर्ष पहले जब महंगाई की दर छह फीसद को पार कर गई तो इसे काबू में लाने के लिए आरबीआइ ने कर्ज को महंगा करने का फैसला किया और कुछ ही महीनों में रेपो रेट (वह दर जिस पर बैंक अतिरिक्त फंड आरबीआइ के पास रख कर कर्ज लेते हैं और इसका इस्तेमाल अल्पकालिक अवधि वाले कर्ज के वितरण में करते हैं) को चार फीसद से बढ़ा कर 6.5 फीसद कर दिया गया था। इसकी वजह से होम लोन, ऑटो लोन आदि की दरों में भी दो फीसद तक महंगे हो गये थे।

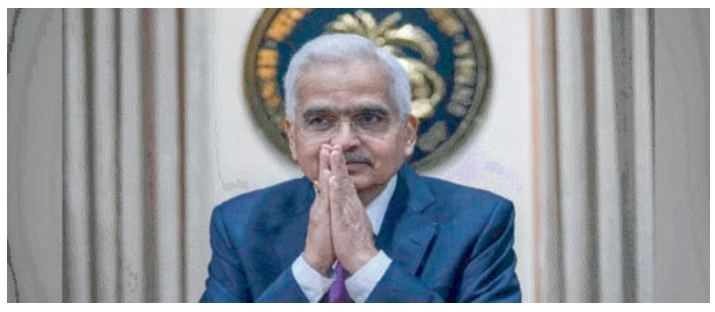

अब महंगाई नीचे आ रही है तो रेपो रेट के कम होने की संभावना है जिससे कर्ज भी सस्ते होंगे।

रेपो रेट को स्थिर रखने के पक्ष में थे एमपीसी के छह सदस्य

आरबीआइ के गवर्नर डॉ. शक्तिकांत दास ने बताया कि एमपीसी के छह सदस्य रेपो रेट को स्थिर रखने के पक्ष में थे। सभी छह सदस्य इस पक्ष में हैं कि विकास के लिए जरूरी फंड की उपलब्धता बनी रहे लेकिन ब्याज दरों को घटाने का फैसला क्रमवार तरीके से हो। महंगाई की तुलना कमरे में बैठे हाथी से करते हुए उन्होंने कहा कि अभी हाथी जंगल में है और उसे वहीं पर लंबे समय तक रखने की कोशिश करनी है। हालांकि उन्होंने वैश्विक हालात को देखते हुए यह भी स्पष्ट कर दिया कि महंगाई पर काबू पाने का काम अभी पूरा नहीं हुआ है क्योंकि सीपीआइ अभी चार फीसद से ज्यादा बनी हुई है। खास तौर पर खाद्य उत्पादों की महंगाई दर के फिर से उभरने का खतरा बना ही हुआ है। लेकिन अच्छी बात यह है कि देश की इकोनमी मजबूत है और ऐसे में आरबीआइ के पास महंगाई को काबू में करने का ज्यादा विकल्प मौजूद है।

इकोनॉमी की है गुलाबी तस्वीर

मौद्रिक नीति समीक्षा करते हुए आरबीआइ गवर्नर डॉ. दास ने देश की आर्थिक स्थिति की भी गुलाबी तस्वीर पेश की है। उन्होंने वर्ष 2024-25 के दौरान देश की आर्थिक विकास दर के 7 फीसद रहने का अनुमान लगाया है। वर्ष 2023-24 में आर्थिक विकास दर के 7.6 फीसद रहने का आंकड़ा जारी किया गया है जो पूर्व के सभी अनुमानों से बेहतर है। विश्व बैंक, आइएमएफ समेत सभी वैश्विक एजेंसियां व रेटिंग कंपनियां भारत की ग्रोथ रेट अनुमान को पहले से बढ़ा रही हैं।

आरबीआइ गवर्नर ने जो डाटा पेश किया है उससे यह भी पता चलता है कि इकोनमी को रफ्तार देने वाले सारे क्षेत्र में सकारात्मक स्थिति है। मैन्युफैक्चरिंग में सुधार है, सेवा क्षेत्र में तेजी है, ग्रामीण क्षेत्रों में भी मांग रफ्तार पकड़ चुकी है जिसका काफी असर होगा। सीमेंट और इस्पात उत्पादन में वृद्धि और पूंजीगत उत्पादों के आयात में वृद्धि बता रहा है कि उत्पादन का एक चक्र स्थापित हो चुका है। वर्ष 2023-24 में बैंकों ने कुल 31.2 लाख करोड़ रुपये का कर्ज दिया है।

डॉ. दास ने कहा है कि, "अभी तक कृषि सेक्टर व ग्रामीण इकोनमी की गतिविधियां बेहतर रहने की संभावना है। रबी की फसल अच्छी हुई है और खरीफ की स्थिति भी बेहतर रहेगी क्योंकि मानसून के सामान्य रहने की बात कही गई है। महंगाई की दर में कमी का भी फायदा होगा क्योंकि दूसरे सेक्टरों में इससे मांग बढ़ेगी।" चिंता सिर्फ वैश्विक घटनाओं को लेकर है जो अनिश्चित हैं।

रेपो रेट में बदलाव न होने का रियल एस्टेट सेक्टर ने किया स्वागत, डेवलपर्स ने कहा- RBI के फैसले से मिलेगा बूस्ट

आरबीआई एमपीसी बैठक में इस बार भी रेपो रेट को स्थिर रखने का फैसला लिया गया था। इस बार भी रेपो रेट को 6.5 फीसदी पर स्थिर रखा था। रियल एस्टेट सेक्टर ने रेपो दरों को 6.5 फीसदी पर अपरिवर्तित रखने के भारतीय रिजर्व बैंक के फैसले का स्वागत किया है। रिजर्व बैंक के फैसलों को लेकर रियल एस्टेट के दिग्गज ने क्या प्रतिक्रिया दी है।

नई दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो दरों को 6.5 फीसदी पर अपरिवर्तित रखने का निर्णय लिया है। आरबीआई के फैसलों का रियल एस्टेट सेक्टर ने स्वागत किया है। बता दें कि पहले ही रियल एस्टेट सेक्टर ने रेपो रेट को स्थिर रखने की उम्मीद जताई थी।

रियल एस्टेट सेक्टर के अलग-अलग दिग्गजों ने आरबीआई के इस कदम को बेहतर बताते हुए अपनी-अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं।

गौड़ ग्रुप के सीएमडी मनोज गौड़ ने कहा, आरबीआई का निर्णय बेहद ही सराहनीय कदम है। भारतीय अर्थव्यवस्था के लगातार मजबूत प्रदर्शन के साथ रेपो रेट को लगातार सातवीं बार स्थिर रखने का निर्णय रियल एस्टेट सेक्टर के लिए अच्छा संकेत होगा। मुद्रास्फीति के आंकड़े अभी भी थोड़ी चिंता का विषय है। यह आरबीआई द्वारा एक अच्छा संतुलन निर्णय है। हमें उम्मीद है कि इस कदम से भारत को मुद्रास्फीति पर लगाम लगाने में मदद मिलेगी जिसके बाद हम देश को कम ब्याज दर वाली व्यवस्था में प्रवेश करते देखेंगे। साथ ही अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट में गिरावट एक चिंता का विषय है जिसके लिए रेपो रेट में कटौती के रूप में राहत की जरूरत है।

काउंटी ग्रुप के डायरेक्टर अमित मोदी ने कहा,

एक बार फिर से आरबीआई ने रेपो दर में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया है जो निश्चित रूप से रियल एस्टेट सेक्टर के लिए फायदेमंद है। आरबीआई का यह निर्णय निवेशकों और घर खरीदारों दोनों के लिए अच्छा साबित होगा। आरबीआई के निर्णय से स्पष्ट संकेत है कि देश की अर्थव्यवस्था लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रही है। हमें यकीन है कि भारत की बढ़ती आर्थिक लचीलापन और मुद्रास्फीति की गिरावट की प्रवृत्ति के साथ रेपो दर में और गिरावट आएगी और पहले से ही रिकॉर्ड तोड़ रहे रियल्टी क्षेत्र की ताकत में वृद्धि होगी।

स्पेक ट्रम मेट्रो के वाइस प्रेजीडेंट अजेंद्र सिंह ने कहा,

लगातार सातवीं बार रेपो दर को 6.50 फीसदी पर बनाए रखने का आरबीआई का निर्णय संभावित बॉयर्स पर वित्तीय बोझ को कम करने की दिशा में एक सकारात्मक कदम है। यह निर्णय कॉमर्शियल सेक्टर में संभावित बॉयर्स को अपनी संपत्ति खरीद के साथ आगे बढ़ने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए अच्छा कदम है। निश्चित रूप से आरबीआई के फैसले से किफायती और मध्य-श्रेणी की कॉमर्शियल प्रोजेक्ट्स को गति मिलेगी।

सिग्नेचर ग्लोबल के फाउंडर प्रदीप अग्रवाल ने कहा,

आरबीआई ने लगातार सातवीं बार रेपो रेट को स्थिर रखकर एक बार फिर अच्छी पहल की है। स्थिर रेपो रेट होम बायर्स के लिए विश्वसनीयता और आत्मविश्वास प्रदान करेगी। निःसंदेह इस स्थिरता का रियल एस्टेट सेक्टर के विकास पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। अंसल हाउसिंग के डायरेक्टर कुशाग्र अंसल ने कहा, रेपो रेट को 6.5 फीसदी पर बनाए रखने के आरबीआई के फैसले से हाउसिंग मार्केट में सकारात्मक राइज की उम्मीद है। बढ़ते हाउसिंग एक्सपेंस के बावजूद, अपरिवर्तित होम लोन दरें संभावित होम बायर्स को कुछ राहत देंगी। जिससे सेक्टर में कॉन्फिडेंस और इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा मिलेगा।

भी के पांडियन को मुख्यमंत्री कार्यालय से निष्कासित किया जाना चाहिए : अनिल बिस्वाल

मनोरंजन सासमल ,
स्टेट हेड उडीशा

भुवनेश्वर। राज्य में आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू कर दी गई है। इस समय सरकारी अधिकारी सीधे तौर पर राजनीतिक आयोजनों में हिस्सा नहीं ले सकते । वर्तमान मुख्यमंत्री के कार्यालय में अधिकारियों की सूची में भि के पांडियन नंबर 1 पर हैं, जो एक बड़ा आश्चर्य है। वह जानकारी अभी भी मुख्यमंत्री कार्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है। पांडियन बाबू बिजेड़ी के नेता हैं । वह बिजेड़ी पार्टी के सभी राजनीतिक कार्यक्रमों का प्रबंधन कर रहे हैं, बिजेड़ी टिकट वितरण उनके निर्देशन में है। पांडियन बाबू वर्तमान में बीजेडी को नियंत्रित कर रहे हैं। यह आश्चर्य की बात है कि आज तक भि के पांडियन को मुख्यमंत्री कार्यालय में एक अधिकारी के रूप में काम दिया जाता है। क्या सरकार यह नहीं जान सकती कि श्री पाडीयान नेता हैं या अधिकारी? यदि श्री पांडियन अधिकारियों की सूची में नंबर 1 पर हैं, तो क्या वह आचार संहिता लागू होने तक सत्तारूढ़ दल के राजनीतिक कार्यक्रम में बने रह सकते हैं? कुछ दिन पहले चुनाव आयोग ने 5 आईपीएस अधिकारियों और 2 आईएएस के खिलाफ कार्रवाई की थी । प्रवक्ता अनिल बिस्वाल ने कहा कि अब प्रमुख शासन सचिव चुनाव आयोग के नियमों का पालन करते हुए भि के पांडियन को तत्काल 5 चेयरमैन के पद से हटाया जाना चाहिए और उनके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जानी चाहिए।

श्री बिस्वाल ने कहा कि ओडिशा में स्वतंत्र, निष्पक्ष चुनाव में मुख्य प्रशासनिक सचिव की बड़ी भूमिका है । ओडिशा शायद एकमात्र ऐसा राज्य है जहां एक व्यक्ति अधिकारी और नेता दोनों है जो सभी राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेता है। चुनावी आचार संहिता का इतना बड़ा उल्लंघन पहले कभी नहीं हुआ। एक दिन पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के चुनाव प्रबंधन में एक अधिकारी के शामिल होने के कारण उनका चुनाव अमान्य कर दिया गया और देश में आपातकाल लगा दिया गया। अब ओडिशा में इंदिरा गांधी की आपात स्थिति का प्रकरण दोहराया जाने वाला है।

हाल ही में, राज्य के प्रमुख आरटीआई कार्यकर्ताओं ने सवाल उठाया कि 74 पुलिस अधिकारी पांडियन बाबू को बचाने के लिए क्यों काम कर रहे थे। लेकिन बड़ी हैरानी की बात यह है कि पांडियन बाबू खुद इस घटना पर चुप थे जबकि भुवनेश्वर पुलिस अपना मुकदमा तैयार कर रही है। लोकतंत्र में हमें सच्चाई का सामना करने की जरूरत है। उसके बिना अगर कोई झूठा मुकदमा दायर किया जाता है तो यह लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है । चुनाव आचार संहिता लागू होने पर पुलिस एक पार्टी नेता के दबाव में क्यों काम कर रही है? पुलिस प्रशासन में यह कहने का साहस है कि दी गई सूचना गलत है। बिना ऐसा किये यह कहना कि हमने सूचना नहीं दी, पुलिस की कमजोरी को दर्शाता है । ओडिशा के लोकतंत्र की हत्या करने की साजिश चल रही है. मीडिया पर हमले हो रहे हैं, आरटीआई कार्यकर्ताओं को परेशान किया जा रहा है और उनके खिलाफ झूठे मामले दर्ज किये जा रहे हैं । श्री बिस्वाल का कहना है कि जनता इस चुनाव में इन सबका उचित जवाब देगी ।

आतंकवाद पर रक्षा मंत्री की दो टूक, बोले- पाक में पनाह लिए आतंकियों को घुसकर मारेगा भारत

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि कोई आतंकवाद को बढ़ावादेगा तो हम उसे नहीं छोड़ेंगे। भारत पड़ोसी देशों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखना चाहता है। आगे उन्होंने कहा कि भारत हमेशा अपने पड़ोसी देशों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखना चाहता है। लेकिन अगर कोई बार-बार भारत को आंखें दिखाएगा भारत आएगा और आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने की कोशिश करेगा।

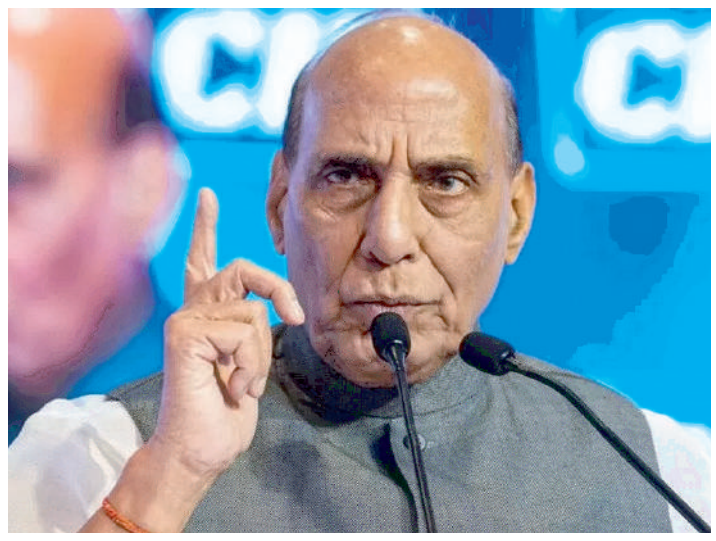

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को कहा कि देश में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने की कोशिश करने के बाद सीमा पार भागने वाले किसी अपराधी को भारत पाकिस्तान में घुसकर मारेगा।

हम पड़ोसी देश में घुसकर मारेंगे

उन्होंने कहा, आतंकी यदि पाकिस्तान भाग जाएगा, तो हम उसे मारने के लिए पड़ोसी देश में घुस जाएंगे। सीएनएन न्यूज18 को दिए साक्षात्कार में रक्षा मंत्री ने कहा, भारत हमेशा अपने पड़ोसी देशों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखना चाहता है। लेकिन अगर कोई बार-बार भारत को आंखें दिखाएगा, भारत आएगा और आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने की कोशिश करेगा, तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं।

राजनाथ सिंह ने कही ये बात

राजनाथ की यह टिप्पणी ब्रिटेन के गार्जियन अखबार द्वारा एक रिपोर्ट प्रकाशित करने के एक दिन बाद आई है। इसमें कहा गया है कि भारत सरकार ने विदेशी धरती पर रहने वाले आतंकियों को खत्म करने की व्यापक योजना के तहत 2020 से अब तक पाकिस्तान में लगभग 20 अपराधियों को मार डाला है।

भारत ने कहा कि यह 'झूठा' दुष्प्रचार

भारत के विदेश मंत्रालय ने रिपोर्ट पर टिप्पणी के लिए रॉयटर के अनुरोध का जवाब नहीं दिया, जबकि पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने टिप्पणी करने से इन्कार कर दिया। पाकिस्तान आतंकियों को पनाह देने से इन्कार करता रहा है। पाकिस्तान ने इस साल की शुरुआत में कहा था कि उसके पास उसकी जमीन पर दो नागरिकों की हत्या में भारतीय एजेंटों के शामिल होने के विश्वसनीय साक्ष्य हैं। इस पर भारत ने कहा कि यह "झूठा और दुर्भावनापूर्ण" दुष्प्रचार है।

भारतीय तटरक्षक बल ने 27 बांग्लादेशी मछुआरों को किया रेस्क्यू, नाव का हुआ था स्टीयरिंग गियर खराब

भारतीय तटरक्षक बल ने 27 बांग्लादेशी मछुआरों की जान बचाई है। अधिकारियों ने शुक्रवार को कहा कि बांग्लादेशी मछुआरों की मछली पकड़ने वाली नाव भारतीय क्षेत्र में बह गई थी। तटरक्षक बल ने कहा कि चार अप्रैल को भारत-बांग्लादेश अंतरराष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा पर गश्त के दौरान भारतीय तटरक्षक जहाज अमोघ ने बांग्लादेशी मछली पकड़ने वाली नाव (बीएफबी) सागर को भारतीय जल क्षेत्र में बहते हुए देखा।

नई दिल्ली। भारतीय तटरक्षक बल ने 27 बांग्लादेशी मछुआरों की जान बचाई है। अधिकारियों ने शुक्रवार को कहा कि बांग्लादेशी मछुआरों की मछली पकड़ने वाली नाव भारतीय क्षेत्र में बह गई थी।

नाव का हुआ था स्टीयरिंग गियर खराब

तटरक्षक बल ने कहा कि चार अप्रैल को दिन में 11: 30 बजे भारत-बांग्लादेश अंतरराष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा पर गश्त के दौरान भारतीय तटरक्षक जहाज 'अमोघ' ने बांग्लादेशी मछली पकड़ने वाली नाव (बीएफबी) 'सागर' को भारतीय जल क्षेत्र में बहते हुए देखा। जांच के लिए टीम को भेजा गया। पता चला कि स्टीयरिंग गियर खराब होने के कारण नाव भारतीय जल क्षेत्र पहुंच गई थी।

भारत ने बांग्लादेश को दी घटना की जानकारी

टीम ने खराबी को ठीक करने की कोशिश की, लेकिन बीएफबी का पतवार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त था। मौसम की अनुकूल स्थिति को देखते हुए बीएफबी को भारत-बांग्लादेश अंतरराष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा पर लाने का निर्णय लिया। इस बीच भारतीय तटरक्षक क्षेत्रीय मुख्यालय ने बांग्लादेश तटरक्षक बल को घटना की जानकारी दी।

बांग्लादेश तटरक्षक बल ने बांग्लादेश तट रक्षक जहाज 'कमरुज्जमां' को बीएफबी को खींचने के लिए तैनात किया।

'कमरुज्जमां' शाम लगभग पौने सात बजे अंतरराष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा के पास पहुंचा।

'अमोघ' ने बांग्लादेशी मछुआरों को बीएफबी के साथ 'कमरुज्जमां' को सौंप दिया।

चीन लाया नई AI टक्नोलॉजी, मात्र 235 रुपए में करवाता है मृत परिजनों से बात

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। हाल ही में चीन से एक अजब मामला सामने आया है। जहां लोग अब अपने मृत परिजनों से जुड़ने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। द गार्डियन की रिपोर्ट के मुताबिक, चीन में सिर्फ 20 युआन यानी भारत के लगभग 235 रुपए में नागरिक अपने मरे हुए रिश्तेदारों का डिजिटल अवतार बना सकते हैं। इसके बाद वह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा बनाए गए अपने प्रिय जनों से वर्चुअल वर्जन में बातचीत कर पाएंगे। यह कदम मृत को याद करने के तरीके में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी के बढ़ते इस्तेमाल को दर्शाता है। 22 साल की बेटी को फिर से जिंदा- ताइवान के एक शख्स ने अपनी 22 साल की बेटी को फिर से जिंदा कर दिया। उसे जिंदा करने के लिए उसने AI का इस्तेमाल किया। उनकी बेटी का साल 2022 में निधन हो गया था। जिसके बाद उसके पिता के पास सिर्फ उसकी बेटी की एक आवाज की रिकॉर्डिंग थी। इसके बाद उन्होंने एआई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया और अपनी बेटी का एक वीडियो बनाया। जिसमें मां के लिए हैप्पी बर्थडे गा रही है। इस वीडियो को बनाने में उन्हें 1

साल से ज्यादा का समय लगा।

आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस इंडस्ट्री- डिजिटल क्लोन बनाने के लिए चीन की दिलचस्पी आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस इंडस्ट्री के तेज से विकास से जुड़ी हुई है। यह इंसानों जैसे दिखने वाले अवतार बना सकते हैं और आंकड़ों के मुताबिक, 2022 में डिजिटल ह्यूमंस की मार्केट वैल्यू 12 बिलीयन युआन दर्ज की गई थी। इसके साथ ही यह भी अनुमान लगाया जा रहा है कि 2025 तक यह चिर गुना बढ़ जाएगा है। चीन की टेक्नोलॉजी में महत्वपूर्ण भूमिका रखने वाले लाइव स्ट्रीम्स, अब प्रोडक्ट्स का प्रचार करने के लिए एआई क्लोन का लगातार इस्तेमाल कर रहे हैं।

डिजिटल कॉपी- चीन के पॉपुलर कंपनी सेंस टाइम ने इस क्षेत्र में अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया है। कंपनी की सालाना आम बैठक में उन्होंने अपने मृत फाउंडर तांग शियाओऊ का भाषण करवाया था। तांग की एक डिजिटल कॉपी बनाई गई। जिसे उनके वीडियो और ऑडियो क्लिप की मदद से तैयार किया गया था। डिजिटल तांग ने कर्मचारियों से संबोधित किया और इससे पता चलता है कि टेक्नोलॉजी तेजी से तरक्की कर रही है और इंसानों जैसे बर्ताव करने में भी नकली रूप दिखा सकती है।

मंच(ABVEM) के चुनाव की हुई अधिसूचना जारी

परिवहन विशेष न्यूज

आगरा। अखिल भारतीय विप्र एकता मंच के राष्ट्रीय प्रवक्ता पंडित आर. सी. कौशिक ने मंच(ABVEM) के चुनाव की अधिसूचना जारी करते हुए अवगत कराया कि हमारे विशाल संगठन का चुनाव, समय से निष्पक्ष व पारदर्शी विधिवत सम्पन्न होगा। 16 राज्यों के ब्राह्मण बन्धु सदस्य चुनाव में भाग लेंगे। मंच के चुनाव आयोग की तैयारिया युद्धस्तर पर चल रही है। मतदान रविवार 5 मई को होगा और मत पत्रों की गणना तथा परिणाम की घोषणा 7 मई को की जाएगी।

वहीं, मुख्य चुनाब अधिकारी प्रोफेसर ए सी शर्मा ने अनुशासनिक तरीके से निस्पक्ष चुनाव कराने का प्रण लिया है। संगठन विगत तीन वर्षों से समाज के उत्थान के लिए संघर्ष कर रहा है और राष्ट्रीय टीम स्व समाज के ब्राह्मण बंधु ही निष्पक्ष व अपने एकल मताधिकार से चुनेंगे और मंच से जुड़े सभी प्रकार की सदस्यता धारक ब्राह्मण बंधु समाज के लिए उत्थान करने राष्ट्रीय वाली टीम चुनेंगे। अखिल भारतीय विप्र एकता मंच मंच जोर शोर से आगे भी एक्शन में

कार्य करेगा।

इस दौरान, प्रोफेसर ए. सी.शर्मा (पूर्व डीन-वडोदरा, गुजरात) मुख्य चुनाव अधिकारी व अन्य चुनाव अधिकारी पं.राम प्रकाश गौड़(अलीगढ़, उ.प्र.), पं.भीकाराम गौड़ (मुरैना,मध्य प्रदेश), पं.वीदोराम शर्मा (भरतपुर राजस्थान), पं.राजवीर शर्मा 'प्रधान'(फरीदाबाद हरियाणा) आदि अधिकारी मंच का चुनाव, समय से निष्पक्ष व पारदर्शी विधिवत रूप से सम्पन्न कराएंगे।

अखिल भारतीय विप्र एकता मंच की राष्ट्रीय कार्यकारिणी का होगा निष्पक्ष चुनाव - प्रोफेसर ए. सी. शर्मा (पूर्व डीन) मुख्य चुनाव अधिकारी

16 राज्यों के ब्राह्मण बन्धु सदस्य लेंगे चुनाव में भाग,

मतदान रविवार 5 मई को होगा और मत पत्रों की गणना तथा परिणाम की घोषणा 7 मई को की जाएगी

मंच से जुड़े सभी प्रकार की सदस्यता धारक ब्राह्मण बंधु चुनेंगे समाज के लिए उत्थान करने राष्ट्रीय वाली टीम- राम प्रकाश गौड़

'भाजपा सत्ता में आई तो खत्म कर देगी आरक्षण', सीएम स्टालिन ने लोकसभा चुनाव को बताया देश का दूसरा स्वतंत्रता आंदोलन

भाजपा आरक्षण और सामाजिक न्याय के खिलाफ है। यदि भाजपा एक बार फिर केंद्र की सत्ता में आई तो आरक्षण खत्म कर देगी। भाजपा सामाजिक न्याय को दफना देगी और हमारे लोगों को 100 साल पीछे ले जाएगी । यह आरोप तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने लगाए। वह शुक्रवार को विक्रवंडी में चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे।

चेन्नई। भाजपा आरक्षण और सामाजिक न्याय के खिलाफ है। यदि भाजपा एक बार फिर केंद्र की सत्ता में आई तो आरक्षण खत्म कर देगी। भाजपा सामाजिक न्याय को दफना देगी और हमारे लोगों को 100 साल पीछे ले जाएगी। यह आरोप तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने लगाए। वह शुक्रवार को विक्रवंडी में चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे।

आरक्षण पर क्या बोले सीएम स्टालिन?

उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान लोकसभा चुनाव को देश का दूसरा स्वतंत्रता आंदोलन करार देते हुए कहा कि इस समय देश बहुत बड़े खतरे का सामना कर रहा है। पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग (एमबीसी), अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यकों के आरक्षण पर खतरा है।

सीएम एमके स्टालिन ने भाजपा पर किया हमला

उन्होंने कहा कि भाजपा आरक्षण के खिलाफ है और यही कारण है कि केंद्र सरकार में पिछड़े वर्ग के तीन प्रतिशत सचिव भी नहीं हैं। केंद्र सरकार द्वारा प्रशासित उच्च शिक्षण संस्थानों में ओबीसी, एससी और एसटी से संबंधित उम्मीदवारों को आरक्षण के माध्यम से प्रोफेसर और सहायक प्रोफेसर जैसे पदों पर नहीं चुना जाता है। यह पिछड़े समाज के साथ अन्याय है।

लोकसभा चुनाव : ईवीएम से कांग्रेस को ऐतराज नहीं, वन नेशन-वन इलेक्शन के विचार को किया अस्वीकार

भारत ने मालदीव के लिए अंडे आलू प्याज चावल गेहूं आटा चीनी और दाल जैसी कुछ वस्तुओं के निर्यात पर प्रतिबंध शुक्रवार को हटा लिया। डीजीएफटी ने कहा कि मालदीव को अंडे आलू प्याज चावल गेहूं का आटा चीनी दाल बजरी और नदी की रेत के निर्यात की अनुमति दी गई है। मालदीव को इन वस्तुओं के निर्यात को किसी भी मौजूदा या भावी प्रतिबंधों से छूट दी जाएगी।

नयी दिल्ली। भारत ने मालदीव के लिए अंडे, आलू, प्याज, चावल, गेहूं आटा, चीनी और दाल जैसी कुछ वस्तुओं के निर्यात पर प्रतिबंध शुक्रवार को हटा लिया। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने अधिसूचना में कहा कि वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते के तहत मालदीव के लिए इन वस्तुओं के निर्यात की मंजूरी दी गई है।

डीजीएफटी ने कहा कि मालदीव को अंडे, आलू, प्याज, चावल, गेहूं का आटा, चीनी, दाल, बजरी और नदी की रेत के निर्यात की अनुमति दी गई है। मालदीव को इन वस्तुओं के निर्यात को किसी भी मौजूदा या भावी प्रतिबंधों से छूट दी जाएगी। अंडे, आलू, प्याज, चीनी, चावल, गेहूं का आटा और दाल के कोटे में भी पांच प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है। नदी के रेत और बजरी कोटा 25 प्रतिशत बढ़ाकर 10 लाख मीट्रिक टन कर दिया गया है।

CAA पर अगाथा संगमा का अहम बयान, कहा- मेघालय को छूट मिली थी, इसलिए किया समर्थन

CAA सीएए यानी नागरिकता संशोधन अधिनियम को लेकर अहम बयान देते हुए एनपीपी नेता अगाथा संगमा ने कहा है कि उन्होंने संसद में सीएए के समर्थन में वोट इसलिए किया था क्योंकि मेघालय को इससे छूट दी गई थी। उन्होंने कहा कि सीएए मेघालय में लागू नहीं होता है इसलिए चिंता का कोई कारण नहीं है। पढ़ें उनका पूरा बयान-

शिलांग। नेशनल पीपुल्स पार्टी की नेता एवं मेघालय के तुरा से निवर्तमान सांसद अगाथा संगमा ने सीएए यानी नागरिकता संशोधन अधिनियम को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मैंने सीएए को समर्थन दिया, क्योंकि मेघालय को इससे छूट दी गई थी।

गौरतलब है कि सीएए पर उनके रुख के लिए उन्हें विपक्षी दलों की आलोचना का सामना करना पड़ा था। समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने अपने रुख को स्पष्ट करते हुए कहा कि अगर गारो हिल्स को सीएए में शामिल किया जाता तो वह विधेयक का समर्थन नहीं करतीं। वह कहती हैं कि सीएए मेघालय में लागू नहीं होता है, इसलिए चिंता का कोई कारण नहीं है।

सांसदों के सुझाव पर दी गई थी छूट

अगाथा संगमा ने बताया कि जब 2019

में सीएए का विधेयक संसद में पेश किया गया था, तब तत्कालीन सांसद और अब के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा के साथ-साथ अन्य सांसदों के सुझाव के आधार पर मेघालय और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों को इसके प्रावधानों से छूट दी गई थी। इससे पहले कॉनराड के संगमा ने भी स्पष्ट किया था कि सीएए मेघालय पर प्रभाव नहीं डालेगा, क्योंकि राज्य का केवल एक छोटा सा हिस्सा इसके दायरे से बाहर रखा गया है।

13 मार्च को जारी हुई थी अधिसूचना

गौरतलब है कि केन्द्र सरकार की ओर से 13 मार्च को सीएए कानून की अधिसूचना जारी की गई थी, जिसके अनुसार 31 दिसंबर 2014 से पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत में आए गैर-मुस्लिम प्रवासियों को भारत की राष्ट्रीयता प्रदान की जाएगी।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक एवं संपादक संजय कुमार बाटला द्वारा इम्प्रेशंस प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग लिमिटेड, सी-18,19,20 सेक्टर 59, नोएडा (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित एवं 3, प्रियदर्शनी अपार्टमेंट ए-4, पश्चिमी विहार, नई दिल्ली- 110063 से प्रकाशित। सम्पर्क : 9212122095, 9811902095 . newstransportvishesh@gmail.com
(इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन पी .आर .बी . एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी) किसी भी कानूनी विवाद की स्थिति में निपटारा दिल्ली के न्यायालय के अधीन होंगे। RNI No :- DELHIN/2023/86499. DCP Licensing Number F.2 (P-2) Press/2023